RNI No. 38189/72

पोस्टिंग - प्रति बुधवार

डाक पंजीयन MP/IDC/58/2024-2026

संस्थापक - स्व. श्री जीवन साहू

युग प्रभात

प्रति गुरुवार | साप्ताहिक | राष्ट्रीय समाचार पत्र | हर कदम पर नए युग के साथ

वर्ष - 55, अंक - 12 | इंदौर, 27 नवम्बर से 3 दिसम्बर 2025 | पृष्ठ-8, कीमत 3 रुपए

अहमदाबाद में 925 अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर

अहमदाबाद।

गुजरात के अहमदाबाद में चंडोला झील के बाद एक और मेगा डिमोलिशन की कार्रवाई हो रही है। शहर के पूर्वी इलाके में स्थित इसनपुर तालाब के आसपास का बने मकान-दुकान ढहाए जा रहे हैं। सोमवार सुबह से शुरू हुई अतिक्रमण हटाने की यह कार्रवाई चार चरणों में होगी।

इसके तहत तालाब किनारे के 925 अवैध मकान-दुकान ढहाई जाएंगी। इन मकानों में 1 हजार से ज्यादा लोग रहते हैं। कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच 20 जेसीबी मशीनों और 500 नगर निगम कर्मचारियों व मजदूरों की टीम लगाई गई है। हालांकि, लोगों का कहना है कि उनके रहने की व्यवस्था किए बिना ही यह कार्रवाई की जा रही है, जिससे हजारों लोग बेघर हो गए हैं।

इसनपुर अहमदाबाद की तीसरा सबसे बड़ी झील है। लोगों ने बांस-बल्लियों से तालाब के बड़े हिस्से पर भी निर्माण कर लिया था। नगर निगम ने मानसून से पहले यहां रहने वालों को नोटिस भेजे थे। लेकिन, नवरात्रि, दशहरा और दिवाली जैसे त्योहारों के चलते तोडफ़ोड़ न कर लोगों को और वक्त दे दिया गया था। इससे पहले यह कार्रवाई 20 नवंबर को होनी थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने और चार दिन का वक्त मांगा था। इसी के चलते कार्रवाई आज सुबह से शुरू हुई।

दिल्ली में बवाल : नक्सली कमांडर के समर्थन में नारेबाजी, पुलिस टीम पर मिर्च स्प्रे से हमला

नई दिल्ली।

राष्ट्रीय राजधानी में हवा की गुणवत्ता लगातार बिगड़ती जा रही है। ऐसे में लोगों ने सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसी को लेकर दिल्ली के इंडिया गेट पर कुछ प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। उन्होंने सड़क पर जाम लगाने की कोशिश की। जब पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उग्र प्रदर्शनकारियों ने पुलिस टीम पर मिर्च स्प्रे से हमला कर दिया। इसमें चार पुलिसवाले घायल हुए हैं। उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। दूसरी ओर पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और इस मामले में 15 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, रविवार को इंडिया गेट पर यह प्रदर्शन दिल्ली-एनसीआर में बेहद खराब वायु गुणवत्ता को लेकर ठोस कदम उठाने की मांग के लिए किया जा रहा था, लेकिन इस प्रदर्शन में मूल तत्व से हटकर भी कुछ विवादित

चार सिपाही जख्मी, 15 लोग गिरफ्तार

बातें सामने आईं। प्रदूषण की समस्या के निस्तारण की मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शन में कुछ प्रदर्शनकारियों ने हाल ही में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए नक्सली कमांडर माडवी हिडमा के पोस्टर उठा रखे थे। इन पोस्टरों में कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा जैसे भड़काऊ स्लोगन लिखे थे। इसके साथ ही उन्होंने नारेबाजी भी शुरू कर दी। दिल्ली पुलिस ने बताया कि इंडिया गेट के पास सी हेक्सागन में चल रहा विरोध प्रदर्शन उस समय उग्र हो गया, जब प्रदर्शनकारियों की भीड़ में शामिल अराजक तत्वों ने सड़क जाम करने की कोशिश शुरू कर दी। भीड़ में शामिल अराजक तत्वों को सड़क की ओर बढ़ता देख पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया।

राजधानी क्षेत्र लगातार तीसरे सप्ताह से गंभीर वायु प्रदूषण की चपेट में

नई दिल्ली।

दिल्ली में प्रदूषण से बुरा हाल है। बीते कई दिनों से दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 400 के पार लगातार बना रह रहा है। इस बीच दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के तहत सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50 फीसदी कर्मियों के साथ काम करने का आदेश दिया है। शेष 50 फीसदी कर्मी घर से काम करेंगे। मतलब यह कि दिल्ली में प्रदूषण के कारण सभी सरकारी, प्राइवेट दफ्तरों में 50 फीसदी कर्मी वर्क फार्म होम करेंगे।

भारतीय सामानों पर लगेगा जीरो टैरिफ, अफगानिस्तानी मंत्री ने कही बड़ी बात

काबुल।

अफ़ग़ानिस्तान के वाणिज्य मंत्री अलहाज नूरुद्दीन ने कहा कि नई दिल्ली और काबुल द्विपक्षीय व्यापार को पुनर्जीवित करने और विस्तारित करने के काफ़ी क़रीब पहुँच गए हैं।

दोनों पक्षों ने वीज़ा और कनेक्टिविटी संबंधी उन मुद्दों को सुलझा लिया है जो व्यापारिक संबंधों में बाधा बन रहे थे। उन्होंने कहा कि दोनों देश अब गर्व की भावना के साथ काम कर रहे हैं और उनका लक्ष्य व्यापार को मौजूदा 1 अरब अमेरिकी डॉलर के स्तर से आगे ले जाना है। नूरुद्दीन ने कहा कि वीज़ा और सीधी उड़ानों से जुड़ी समस्याओं का समाधान कर लिया गया है, जिससे व्यापारियों और यात्रियों की सुगम आवाजाही का रास्ता साफ़ हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि चाबहार लिंक, ज़मीनी मार्गों और हवाई गलियारे पर भी बातचीत आगे बढ़ रही है।

मंत्री ने कहा कि दोनों देश व्यापार पर संयुक्त कार्य समूह को सक्रिय करने पर सहमत हुए हैं, जिसके तहत प्रत्येक पक्ष एक-दूसरे की राजधानी में एक वाणिज्यिक अटैची तैनात करेगा। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि यह एक महीने के भीतर लागू हो जाएगा। व्यापारिक जुड़ाव बढ़ाने के लिए, भारत और अफ़ग़ानिस्तान एक संयुक्त वाणिज्य मंडल स्थापित करेंगे और व्यापार विस्तार को बढ़ावा देने के लिए टैरिफ़ में पारस्परिक रूप से कमी की जाएगी।

कर्नाटक में जारी है सत्ता के लिए संघर्ष, डीके के कई और विधायक दिल्ली पहुंचे, राहुल विदेश में

बेंगलुरु।

कर्नाटक में मुख्यमंत्री परिवर्तन के मुद्दे पर सत्तारूढ़ कांग्रेस के भीतर सत्ता संघर्ष लगातार जारी है। इस बीच उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का समर्थन करने वाले विधायकों का एक और समूह पार्टी आलाकमान से मिलने के लिए दिल्ली में डेरा डाले हुए है। कांग्रेस पार्टी सूत्रों ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार, करीब छह विधायक रविवार रात दिल्ली पहुंचे हैं। सूत्रों ने बताया कि शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग को लेकर जल्द ही कुछ और विधायकों के दिल्ली आ सकते है।

खबरों के अनुसार, यह मामला 2023 में हुए सत्ता-साझेदारी समझौते पर आधारित है, इसके तहत सिद्धरमैया को ढाई साल (20 नवंबर तक) मुख्यमंत्री रहना था और इसके बाद पूरी कमान उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को मिलनी थी।

पार्टी सूत्रों ने बताया कि जो विधायक दिल्ली में हैं, उसमें एच सी बालकृष्ण (मगदी), के एम उदय (मद्दूर), नयना मोटाम्मा (मुदिगेरे), इकबाल हुसैन (रामनगर), शरथ बाचेगौड (होसाकोटे) और शिवगंगा बसवराज (चन्नागिरी) शामिल हैं।

कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे अभी बेंगलुरु में हैं और वह जल्द ही दिल्ली पहुंचने वाले हैं। वहीं, कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी के भी विदेश यात्रा से लौटने की संभावना है। शिवकुमार का समर्थन करने वाले करीब 10 विधायकों ने पिछले सप्ताह नई दिल्ली जाकर खरगे से मुलाकात की थी। राज्य में कांग्रेस सरकार ने 20 नवंबर को अपने ढाई साल पूरे कर लिए। हालांकि, शिवकुमार ने तब कहा था कि उन्हें विधायकों के खरगे से मिलने के लिए दिल्ली जाने की जानकारी नहीं है। शिवकुमार का समर्थन करने वाले विधायकों के दिल्ली जाने के बाद, मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बेंगलुरु स्थित खरगे के आवास पर उनके साथ एक घंटे से ज्यादा समय तक बैठक की।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, सिद्धरमैया अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल पर जोर दे रहे हैं, वहीं शिवकुमार चाहते हैं कि पार्टी पहले नेतृत्व परिवर्तन पर फैसला करे। पार्टी के कई अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, अगर कांग्रेस आलाकमान मंत्रिमंडल में फेरबदल को मंजूरी दे देता है, तब यह संकेत होगा कि सिद्धरमैया पांच साल का अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं, जिससे शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं कम हो जाएगी।

प्रदेशभर में बनेंगे अत्याधुनिक फायर ब्रिगेड, खर्च होंगे 400 करोड़

भोपाल । अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। करीब 400 करोड़ रुपये की लागत से पूरे प्रदेश के नगरीय निकायों में 36 आधुनिक फायर स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके लिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर फंड आवंटित किया गया है। फायर स्टेशन बनाने के साथ नई फायर गाड़ियां खरीदी जाएंगी और उपकरण भी आधुनिक तकनीक के होंगे, ताकि आग लगने की घटनाओं पर जल्दी और प्रभावी तरीके से नियंत्रण पाया जा सके। इसके साथ ही सरकार राज्य स्तरीय फायर कंट्रोल रूम भी बनाएगी, जहां से पूरे प्रदेश के सभी फायर स्टेशनों को जोड़ा जाएगा। इससे आगजनी की घटनाओं पर त्वरित निगरानी और समन्वय सुनिश्चित होगा। नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेज दिया है, जिसकी मंजूरी के बाद काम शुरू हो जाएगा।

हर फायर स्टेशन लगभग 2 एकड़ जमीन में बनेगा। एक स्टेशन पर दो दमकल गाड़ियां रहेंगी। एक बड़ी और एक छोटी। प्रति स्टेशन निर्माण पर करीब 2 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें फायर स्टेशन + फायर गाड़ियां पर 119 करोड़, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण पर 20 करोड़, आधुनिक फायर उपकरण पर 178 करोड़, कंट्रोल रूम सुदृढ़ीकरण पर 20 करोड़, अन्य विशेष आवश्यकताएं पर 59 करोड़ खर्च होंगे। यानी कुल 398 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें 75% राशि लगभग 297 करोड़ केंद्र सरकार और 25% राशि करीब 100 करोड़ राज्य सरकार देगी।

उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ सम्मानित

इंदौर । इंदौर जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य को गति प्रदान करते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को आज कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिवम वर्मा द्वारा कलेक्टर कार्यालय में सम्मानित किया गया।

कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने बीएलओ श्री संजय रावत और नीरज चौधरी को शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण करने और उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए दस-दस हजार रुपये की नगद राशि, शाल एवं श्रीफल प्रदान कर सम्मानित किया। इसी तरह सम्मानित होने वाले अन्य अधिकारियों में श्री अशोक शर्मा, श्री विनोद शर्मा, श्री विजय पटेल शामिल हैं। सभी अधिकारी शिक्षा विभाग से हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वर्मा ने इन अधिकारियों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि उनकी कर्मठता और परिश्रम से जिले में पुनरीक्षण कार्य समयबद्ध रूप से गति पकड़ रहा है। उन्होंने जिले के अन्य बीएलओ को भी प्रेरित करते हुए अपेक्षा व्यक्त की कि वे भी इसी समर्पण के साथ कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ को इसी प्रकार सम्मानित किया जाएगा। सांवेर विधानसभा क्षेत्र के नाहर झाबुआ की बीएलओ श्रीमती रीना निगवाल ने भी शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया है, इन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर श्री नवजीवन विजय पवार, एसडीएम सांवेर श्री घनश्याम धनगर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य 2625 बूथों पर एक साथ संचालित हो रहा है। बीएलओ घर-घर जाकर गणना पत्रक वितरित कर मतदाता सूची के अद्यतन का कार्य कर रहे हैं। कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने नागरिकों से अपील की है कि वे बीएलओ को आवश्यक जानकारी और सहयोग प्रदान कर इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें।

फरार इनामी वारंटी गिरफ्तार

भोपाल(ईएमएस)। थाना रातीबड़ पुलिस ने तीन साल पुराने चोरी के मामले में फरार चल रहे फरार ईनामी स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी रातीबड़ रास बिहारी शर्मा ने बताया की चांद नवाब पिता शब्बीर (25) निवासी तीन साल पुराने चोरी के मामले में फरार चल रहा था।

सिल्क इंडिया में 'वैडिंग स्पेशल' हेंडलूम साड़ियों का कलेक्शन

इंदौर । बास्केटबॉल काम्प्लेक्स में आयोजित एग्जीबिशन में 2026 के नए ट्रेंड्स की सिल्क साड़ियाँ इंदौर 20 नवंबर 2025 - सर्दियों के आगमन के साथ एक बार फिर विंटर वैडिंग सीजन की शुरुआत हो गयी है। वैवाहिक मुहूर्तों के अवसर पर वैवाहिक सिल्क साड़ियों की विशाल श्रृंखला लेकर एक बार फिर सिल्क इंडिया एग्जीबिशन शहर में है।

बास्केटबाल काम्पलेक्स, रेसकोर्स रोड, इंदौर में यह एग्जीबिशन गुरुवार 20 नवंबर से शुरु हो गई है। 11 दिन के लिए आयोजित यह साड़ी सेल रविवार 30 नवंबर तक जारी रहेगी। देश के प्रसिद्ध बुनकर अपनी सदियों से सहेजी गई हेण्डलूम की विरासत को नये डिजाईनों के साथ यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। सिल्क की यही खुबसूरत साड़ियाँ विवाह समारोहों, पारिवारिक आयोजनों की शोभा बढ़ाती हैं। भारतीय बुनकरों की महीनों की मेहनत और बेजोड़ कलाकारी साड़ियों को अनमोल बनाती है। साड़ियों की लगभग 50 हजार वैरायटी यहां प्रदर्शित की जा रहीं हैं।

20 नवंबर से 30 नवंबर तक प्रतिदिन सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक आयोजित की जा रही सिल्क इंडिया सेल में देश के विविध स्थानों की लोकप्रिय वैरायटी की मनमोहक साड़ियाँ एवं ड्रेस मटेरियल पेश किए गए हैं।

तरह-तरह के डिजायन्स, पैर्टन्स, कलर कॉम्बिनेशन में इन साड़ियों का व्यापक खजाना यहाँ उपलब्ध है। उड़ीसा आर्ट एण्ड क्रॉफ्ट की ओर से आयोजित इस सेल में देश के विविध प्रांतों की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय वैरायटी का चुनिंदा वैवाहिक संग्रह प्रदर्शित किया गया है। यहाँ प्रस्तुत हर साड़ी एवं ड्रेस मटेरियल अपने आप में अद्वितीय और मनमोहक है।

निगम ने हटाए विभिन्न क्षेत्रों से अतिक्रमण

भोपाल ।नगर निगम द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अतिक्रमणों एवं अवैध निर्माणों को हटाने की कार्यवाही निरंतर जारी है। इसी तारतम्य में निगम के अतिक्रमण निरोधक दस्ते के दलों ने सीएम हेल्प लाईन, कॉल सेंटर व अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों के निराकरण तथा निगम की नियमित कार्यवाही के तहत विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में अतिक्रमण कर लगाई गई कंबल, जैकेट, सब्जी, हेलमेट आदि की दुकानों के अलावा ठेले, गुमठी, पान पार्लर, काउंटर, बोर्ड हटाए साथ ही आवागमन में बाधक दो पहिया, चार पहिया वाहन हटाते हुए ठेले, चेन, जाली, टेबिल, कांटे, स्टैण्ड आदि को जप्त किया। निगम अमले ने अनेक क्षेत्रों में अवैध रूप से लगाई गई चिकन की दुकानों, अवैध रूप से बनें टपरे, चबूतरे आदि को भी हटाया।

निगम आयुक्त श्रीमती संस्कृति जैन के निर्देश पर निगम के अतिक्रमण निरोधक दस्ते के दलों ने शुक्रवार को कोलार जेके हास्पिटल, डीमार्ट, चूना भट्टी, सर्वधर्म कालोनी, निर्मलादेवी गेट, सौम्या चैराहा, नारायण नगर, बावड़िया फाटक, होशंगाबाद रोड, दानिश चैराहा, भारतमाता चौराहा, भदभदा, जवाहर चौक, न्यू मार्केट बेतवा

अपार्टमेंट, 10 नंबर स्टॉप, गवर्मेंट प्रेस, पर्यावास भवन, पुरानी जेल, पातरा पुल, इस्लामपुरा, नारियलखेड़ा, करोद चैराहा, विश्वकर्मा नगर, गांधी नगर बस स्टैण्ड, अब्बास नगर, हमीदिया रोड, रेल्वे स्टेशन प्लेटफार्म नं.06, रायसेन रोड, अप्सरा टॉकीज, प्रभात चैराहा, अशोका गार्डन, पुष्पा नगर, चांदबड़ आदि क्षेत्रों में अतिक्रमणों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए सर्वधर्म कालोनी क्षेत्र में फुटपाथ पर अतिक्रमण कर लगाई गई कंबल की दुकानें, हमीदिया रोड फुटपाथ से जूते की दुकानें सहित अन्य स्थानों से बड़ी संख्या में ठेले, गुमठी आदि को हटवाया। निगम अमले ने गांधी नगर अब्बास नगर रोड पर अवैध रूप से संचालित 01 चिकन की दुकान, बावड़िया फाटक के पास से 01 अवैध रूप से निर्मित टपरा तथा विश्वकर्मा नगर में अवैध रूप से बना 01 चबूतरा तोड़ने की कार्यवाही की। निगम अमले ने नारियलखेड़ा रोड से आवागमन में बाधक 02 चार पहिया वाहन तथा नारायण नगर रोड से 05 चार पहिया वाहन हटवाने की कार्यवाही की। उपरोक्त कार्यवाही के दौरान निगम अमले ने 04 ठेले, 04 टेबिल, 02 मुर्गा जाली, 02 इलेक्ट्रिक कांटे, 02 लोहे की चेन, 01 स्टैण्ड सहित अन्य प्रकार का सामान जप्त किया।

लव जिहाद के खिलाफ सकल हिंदू समाज ने धरना देकर जताया विरोध

भोपाल । राजधानी भोपाल में लव जिहाद की घटनाओ को लेकर अपना विरोध जताते हुए सकल हिंदू समाज ने शुक्रवार को कलेक्टोरेट के बाहर धरना दिया। इस दौरान लोगों ने बीते दिनो हुई मॉडल खुशबू अहिरवार की मौत के मामले की उच्चस्तरीय जॉच कर उसके परिवार वालो को न्याय दिलाने के साथ ही उसके परिवार को सुरक्षा दिये जाने की मांग भी की। जानकारी के अनुसार संत शिरोमणि गुरु रविदास विश्व महापीठ मध्यप्रदेश के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) सूरज केरो के नेतृत्व और एवं सकल हिंदू समाज के तत्वावधान में बड़ी संख्या में लोगो ने कलेक्टोरेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। सकल हिंदू समाज का कहना है, कि खुशबू की हत्या की गई है। उसके दोषियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। धरने के बाद एडीएम अंकुर मेश्राम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया।

नक्सली हिडमा के एनकाउंटर पर मप्र में सियासत गर्म, दिग्विजय ने लगाए आरोप

भोपाल ।छत्तीसगढ़ के कुख्यात और इनामी नक्सली माड़वी हिड़मा की मौत के बाद मध्य प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा एनकाउंटर की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जाने के बाद पूरा राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है।

दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर बस्तर की सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोढ़ी का वीडियो साझा किया। वीडियो में सोढ़ी दावा कर रही हैं कि हिड़मा और उसके साथियों की मौत एनकाउंटर नहीं, बल्कि योजनाबद्ध हत्या थी। उनके मुताबिक पुलिस की टाइमलाइन संदिग्ध है। छह लोगों को पकड़कर मारा गया। ग्रामीणों का कहना है कि घटना स्थल पर नक्सली मौजूद ही नहीं थे। सोढ़ी अंतिम संस्कार में भी शामिल हुई थीं और न्यायिक जांच की मांग कर रही हैं।

सोढ़ी का वीडियो शेयर करते ही BJP ने दिग्विजय सिंह पर तीखा प्रहार किया। मंत्री विश्वास सारंग ने भी आरोप लगाया कि दिग्विजय सिंह लगातार राष्ट्र विरोधी तत्वों का समर्थन करते नजर आते हैं। शहीद जवान पर एक शब्द नहीं, लेकिन नक्सली के लिए संवेदना! वे तुष्टीकरण की राजनीति में इतने आगे बढ़ चुके हैं कि देशद्रोही ताकतों का बचाव आदत बन गई है। सारंग ने दिग्विजय के बयान को देशहित के खिलाफ बताया।

सांसद आलोक शर्मा ने कहा जब देश के जवान शहीद होते हैं, तब दिग्विजय चुप रहते हैं, लेकिन नक्सलियों और आतंकवादियों पर सवाल उठाने में सबसे आगे रहते हैं। इसी मानसिकता के कारण कांग्रेस बार-बार हार का सामना कर रही है।

मैं हिंसा के विरोध में हूं, मुद्दा आदिवासी अधिकारों का

दिग्विजय सिंह ने स्पष्ट किया कि वे नक्सली हिंसा के खिलाफ हैं, लेकिन समाधान बातचीत और आत्मसमर्पण की नीति से निकल सकता है। उन्होंने कहा कि असल मुद्दा आदिवासियों के सामाजिक-आर्थिक अधिकारों का है। PESA कानून देश के शेड्यूल्ड एरिया में लागू नहीं किया जा रहा, जिससे आदिवासियों के अधिकार कमजोर हुए हैं। नक्सल क्षेत्रों के आदिवासियों के पास दस्तावेज कैसे होंगे? मतदाता सूची में नाम न जुड़ने का मतलब है कि उनकी नागरिकता खतरे में है। उन्होंने BJP पर आरोप लगाया कि वह आदिवासी हितों के मुद्दों से हमेशा दूरी बनाकर चलती रही है।

एनकाउंटर की पृष्ठभूमि

18 नवंबर को आंध्र प्रदेश के अल्लुरी सितारामा राजू जिले में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ में हिड़मा, उसकी पत्नी राजे और चार अन्य नक्सली मारे गए थे। हिड़मा पर कई बड़े हमलों के आरोप थे और वह सुरक्षा एजेंसियों की टॉप सूची में शामिल था।

फर्जी मतदाता के नाम पर असली का नाम नहीं काटने देंगे

इंदौर । विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 के कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शहर कांग्रेस के अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने सभी एजेंट से साफ शब्दों में कहा कि फर्जी मतदाता के नाम पर कहीं भी असली मतदाता का नाम नहीं कटना चाहिए।

चौकसे ने आज परदेशीपुरा क्षेत्र के धर्मशाला में आयोजित इस बैठक में कहा कि मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का कार्य करने के पीछे भाजपा की जो मंशा है उससे हम सभी वाकिफ है। हमें यह ध्यान रखना है कि भाजपा अपने षड्यंत्र में सफल नहीं हो पाए। कहीं भी फर्जी मतदाता के नाम पर असली मतदाताओं के नाम नहीं कटना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें यह ध्यान देना होगा कि जो लोग क्षेत्र छोड़कर जा चुके हैं अथवा जिनकी मृत्यु हो गई है उनके नाम अवश्य इस सूची से कट जाएं।

विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी पार्षद राजू भदोरिया ने कहा कि हम सभी को पूरी मुस्तैदी के साथ इस काम को अंजाम देना है। इस काम में गड़बड़ी करके ही भाजपा फर्जी वोटो की व्यवस्था करती है। ऐसी व्यवस्था करने की कोशिश को हमें इस बार नाकाम कर देना है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता राजेश चौकसे ने कहा कि यह काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी का काम है।<

वीआईपी रोड के अवैध निर्माण का मामला

शिकायत का सहारा, खुद अवैध निर्माण लेकर बैठे, कार्यवाही पर पुलिस को झूठी शिकायत

भोपाल। वीआइपी रोड की चिन्हित शत्रु संपत्ति के मामले में अब चोरी और सीनाजोरी के हालात बनते नजर आ रहे हैं। यहां किए गए अवैध निर्माण की शिकायत पर कार्यवाही करने पहुंचे निगमकर्मी के खिलाफ पुलिस को झूठी शिकायत कर दी गई है। सरकारी काम में बाधा डालने के इस मामले को पुलिस ने भी झूठा करार दिया है।

सूत्रों का कहना है कि मामला उस समय हुआ, जब नगर निगम की भवन अनुज्ञा शाखा के एक कर्मचारी ने वीआईपी रोड स्थित नशेमन नामक मकान पर दस्तक दी। निगम को इसके अवैध निर्माण और फर्जी दस्तावेजों की शिकायत मिली थी। इस शिकायत के सत्यापन करने पहुंचे निगमकर्मी से मकान मालिक इस बात से मुकर गए कि वह शिकायत से संबंधित स्थान पर है। निगमकर्मी के वहां से हटने के कुछ देर बाद ही कोहेफिजा थाने में एक शिकायत कर दी गई। इस शिकायत में निगमकर्मी पर आरोप लगाए गए हैं कि उसने मकान मालिक को धमकाया और अभद्रता की है।

सूत्रों का कहना है कि पुलिस शिकायत पर निगमकर्मी कोहेफिजा थाने पहुंचे थे। उन्होंने झूठी शिकायत का हवाला देते हुए मकान मालिक मोहम्मद बशीर से मामले के समय के वीडियो फुटेज उपलब्ध कराने की बात कही। इससे बशीर मुकर गए और उन्होंने फुटेज देने से इंकार कर दिया।

अवैध निर्माण की शिकायत पर कार्यवाही करने पहुंचे निगमकर्मी पर बशीर, उनके बेटे और परिजनों ने झूठे आरोप लगाए हैं। उसके सरकारी काम में भी बाधा पहुंचाई गई है। साथ ही थाने में झूठी शिकायत कर अपमानित भी किया गया है। इस मामले को लेकर अब वे भी बशीर और उनके परिजन के खिलाफ शिकायत करेंगे। इसके लिए उन्होंने अपने विभाग से अनुमति मांगी है।

क्या है मामला

शत्रु संपत्ति में शामिल वीआईपी रोड स्थित जमीनों में एक निर्माण नशेमन नामक मकान का भी है। हिबानामा, इनायतनामा, भवन अनुज्ञा, नक्शा सहित भवन से संबंधित सभी दस्तावेज फर्जी हैं। इन्हें लेकर कई अदालती मामले भी चल रहे हैं। इन मामलों में भी मकान मालिक अदालत को गुमराह कर चुके हैं। इसको लेकर नगर निगम को घेरे में लेते हुए सीएम से शिकायत की गई थी।

नोटिस नहीं, काम शुरू नहीं करने वाले ठेकेदारों पर करें कड़ी कार्रवाई- मैयर

मैयर के अलावा कमिश्नर ने भी शहर के कई वार्डों का किया दौरा, अफसरों को दिए निर्देश

इन्दौर ।शहर की सफाई व्यवस्था से लेकर वार्डों में होने वाले विकासकार्यों की स्थिति देखने के लिए शुक्रवार को महापौर और कमिश्नर अलग अलग क्षेत्रों में दौरा करने निकले। इस दौरान छीपा बाखल क्षेत्र में ठेकेदार ने लाईनें बिछाने का काम शुरू नहीं किया तो उन्होंने अफसरों को फटकार लगाते हुए कहा कि नोटिस देना ही प्रयास नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई कर ब्लेकलिस्टेड करें और टेंडर निरस्त करें। वहीं तंबोली बाखल में बेकलाईनों में गाद पड़ी होने पर उन्होंने अफसरों से पूछा कि इसे एक साल बाद हटाएंगें। वहीं दूसरी ओर कमिश्नर ने भी स्कीम १३६ में ६ गार्डन अहिल्या वन के रूप में विकसित करने के लिए निगम द्वारा दिए गए थे, लेकिन एजेंसी ने वहां काम शुरू नहीं किया तो उन्होंने संबंधित एजेंसी को हटाने के निर्देश दिए।

महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने शुक्रवार सुबह झोन क्रमांक 20 के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 8 के छिपा बाखल, अहिल्या पलटन, चौथी पलटन, तंबोली बाखल, मल्हारगंज एवं अन्य आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों एवं

स्थानीय नागरिकों साथ थे। इस दौरान गोराकुंड से सुभाष मार्ग के मध्य बिछाई जाने वाली ड्रेनेज लाइन के संबंध में जानकारी ली तो पता चला कि काम ही शुरू नहीं हुआ है। इस पर उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई। इसके बाद छिपा बाखल क्षेत्र के निरीक्षण में महापौर ने ड्रेनेज लाइन, जलप्रदाय लाइन एवं सड़क निर्माण कार्यों में हो रही देरी पर अधिकारियों से पूछताछ की। अधिकारियों ने बताया कि ठेकेदार को कार्य आदेश जारी किया जा चुका है, बावजूद इसके उसने काम शुरू नहीं किया, जिस पर उसे नोटिस भी जारी किया गया है। इस पर महापौर भड़क गए और कहा कि आपका काम सिर्फ नोटिस देना नहीं है, काम करवाना भी है। यदि ठेकेदार काम नहीं करता है तो उसे ब्लैक लिस्ट करें और टेंडर कैंसिल करें। चौथी पलटन क्षेत्र में बोरिंग कार्य पूर्ण होने के बाद भी जलप्रदाय लाइन न डाले जाने पर महापौर श्री भार्गव ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने निर्देश दिए कि आज ही बोरिंग से जल प्रदाय कनेक्शन लाईन बिछाने का काम शुरू किया जाए।

तंबोली बाखल क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान महापौर ने ड्रेनेज लाइन सही प्रकार से न डाले जाने और ड्रेनेज सफाई होने के बाद भी गार्ड न उठाए जाने पर असंतोष जताते हुए अधिकारियों पर सख्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि क्या एक साल बाद गली से गाद उठाएंगे? महापौर ने क्षेत्र में कचरा एवं गंदगी फैलाने वालों पर सख्त चालानी कार्रवाई करने एवं आवश्यकतानुसार पेनल्टी लगाने के निर्देश दिए।

वहीं दूसरी ओर निगम कमिश्नर दिलीप कुमार यादव ने स्कीम नम्बर 136 में निरीक्षण किया। आईडीए के खाली प्लाटों पर कचरा फेंका जा रहा था खाली प्लॉट पर प्री कास्ट से बाउंड्री वॉल बनाने के आई डी ए के अधिकारियों को कहा गया गया। इसके बाद स्कीम नम्बर 136 में सीएसआर से 6 गार्डन अहिल्या वन के रूप में विकसित करने के लिए दिये गए हैं किंतु एजेंसी द्वारा विकसित नहीं किए जाने पर विकसित करने के लिए नोटिस देने ओर विकसित नहीं करने पर निगम द्वारा वापस लेने के निर्देश दिए। आईडीए द्वारा एम आर 11 बायपास से ए बी रोड तक रोड निर्माण का कार्य किया जा रहा है उक्त रोड पर अमृत योजना के अंतर्गत सीवरेज का नेटवर्क डाला जाना है रोड निर्माण के साथ ही सीवरेज नेटवर्क डालने का कार्य करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही स्कीम नम्बर 136 में आईडीए की भूमि पर अतिक्रमण का निरिक्षण किया ओर अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए।

5 साल बाद शुरू होगी लिफ्ट

इंदौर ।एम टी एच कंपाउंड स्थित नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के सैकड़ो कर्मचारियों के साथ-साथ मरीजों को भी 5 साल बाद राहत मिलने वाली है यहां लिफ्ट सुधारने का काम शुरू हो गया है पिछले 5 वर्षों से यह लिफ्ट बंद थी और बजट के अभाव के साथ-साथ दूसरी विसंगतियों के चलते पिछले 5 सालों से लिफ्ट सुधारने की प्रक्रिया ठंडे बस्ते में पड़ी हुई थी।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एम टी एच कंपाउंड स्थित स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय और नगर निगम भवन लोकसेवा केंद्र मैं संचालित होने वाली लिफ्ट पिछले 5 सालों से बंद पड़ी हुई थी । स्वास्थ्य विभाग सूत्रों का कहना है कि इसके बंद होने के कारण ऊपरी मंजिलों पर तीसरे माले पर संचालित होने वाले स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न शाखाओ में मरीज और कर्मचारी भी जो की वृद्ध है। पहुंच नहीं पाते थे। इसको लेकर कई बार स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी नगर निगम को पत्र व्यवहार किया गया लेकिन मामला वहीं ढाक के तीन पात ही रहा लेकिन अब स्थिति में सुधार होने जा रहा है।

सूत्रों का कहना है कि अभी यहां सभी संचालित होने वाली लिफ्ट को सुधर जा रहा है और नए सेटअप में ढाला जा रहा है।

5 वर्ष बाद लिफ्ट के सुधार होने से स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी के साथ-साथ नगर निगम और यहां संचालित होने वाले अन्य शासकीय विभागों के कर्मचारियों में भी हर्ष व्याप्त है।

कॉलेज के विद्यार्थी पोर्टल पर फॉर्म भरने में करेंगे सहयोग

इंदौर । जिले में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशानुसार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य तेज गति से जारी है। इस कार्य को समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिवम वर्मा के निर्देशन में अभिनव पहल करते हुए नवाचार किया जा रहा है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कॉलेज विद्यार्थियों को भी निर्वाचन की सहायक प्रक्रिया से जोड़ा जा रहा है।

इसी संदर्भ में आज कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिवम वर्मा ने जिले के शासकीय और अशासकीय कॉलेजों के संचालकों की बैठक ली। कलेक्टर कार्यालय में सम्पन्न हुई इस बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी और अपर कलेक्टर श्री नवजीवन विजय पवार, सहायक उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अजीत श्रीवास्तव, मास्टर ट्रेनर श्री आर.के. पाण्डे सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने जिले में चल रही मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया की जानकारी दी और सभी से सक्रिय सहयोग की अपेक्षा की। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (स्ढ्ढक्र) की कार्यवाही पूरी गंभीरता और गति के साथ संचालित की जा रही है। इसी प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने एक अभिनव पहल की है, जिसके तहत कॉलेज विद्यार्थियों को भी निर्वाचन की सहायक प्रक्रिया से जोड़ा जा रहा है। कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि युवा विद्यार्थी देश का उज्ज्वल भविष्य हैं और उन्हें निर्वाचन जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया का अनुभव होना चाहिए। इसी उद्देश्य से आज जिले के सभी कॉलेज संचालकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कॉलेज संचालकों से अनुरोध किया गया कि वे अपने यहां से इच्छुक छात्र-छात्राओं एवं कुछ फैकल्टी सदस्यों को इस कार्य में सहयोग हेतु उपलब्ध कराएँ। इससे न केवल युवाओं को उपयोगी अनुभव मिलेगा, बल्कि निर्वाचन कार्यों के लिए एक सक्षम और ऊर्जावान वर्कफोर्स भी तैयार होगी। उन्होंने बताया कि अभिनव पहल के तहत शहर की विभिन्न रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ में हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे, जिन पर प्रशिक्षित विद्यार्थी नागरिकों को भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) पोर्टल पर फॉर्म भरने में मार्गदर्शन करेंगे। इन डेस्क पर विद्यार्थी, बीएलओ के साथ मिलकर फॉर्म भरवाने, सुधार कराने तथा डिजिटलाइजेशन संबंधी कार्यों में सहायता करेंगे। इससे शहरी क्षेत्र में मतदाता सूची पुनरीक्षण की गति और गुणवत्ता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।<

सम्पादकीय

आरोपों की राजनीति में झूलता लोकतंत्र

भारत की राजनीति में कौन सी स्थिति कब पैदा हो जाए, कोई यकीनी तौर पर कह नहीं सकता। कभी सत्ता से बेदखल करने के लिए कांग्रेस के विरोध में राजनीतिक दल एकत्रित होते थे, अब यह दृश्य पूरी तरह से विपरीत होता जा रहा है। अब भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के लिए राजनीति की जा रही है। इतना ही नहीं इसके लिए लोकतांत्रिक देश में आरोप और प्रत्यारोप का अभियान सा भी चलता दिखाई दे रहा है। आज की राजनीति के लिए सबसे गंभीर बात यह है कि यह सारे आरोप केवल और केवल प्रायोजित जैसे ही लगते हैं। अभी हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चलाए जा रहे प्रचार अभियान के अंतर्गत विपक्षी राजनीतिक दलों ने केन्द्र की भाजपा सरकार पर वोट चोरी का गंभीर आरोप लगाकर चुनावी दृश्य को अपने रंग में रंगने का प्रयास किया। इस बारे में सबसे गंभीर तथ्य यह भी है कि जो इस दुनिया से चले जाते हैं, उनके वोट हर वर्ष कटते ही हैं और जो युवा अपनी 18 वर्ष की उम्र पूर्ण कर लेते हैं, उनके नाम भी जुड़ते हैं। वैधानिक स्थिति में दो स्थानों पर नाम होना एक बड़ा अपराध होता है। यहां सबसे बड़ा सवाल यही है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने का काम विधिवत तरीके से चुनाव आयोग ही करता है, लेकिन राजनीतिक दल इसके लिए सीधे तौर पर भाजपा को जिम्मेदार बताने का प्रयास किया जा रहा है। यह आरोप लगाना ही यह प्रमाणित करता है कि वोट चोरी का मामला पूरी तरह से राजनीतिक है, लोकतांत्रिक नहीं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत किए जा रहे कार्यों पर सवाल खड़े करना लोकतंत्र को कमजोर करने जैसा ही है। बिहार में जो आरोप लगाए गए, उनको प्रमाणित करने का सामर्थ्य अगर किसी के पास है तो उन प्रमाणों के साथ ही आरोप लगाना चाहिए। अगर प्रमाण नहीं है तो उन आरोपों को तथ्यहीन ही माना जाएगा। वोट चोरी का आरोप भी तथ्यहीन ही माना जा रहा है। क्योंकि चुनाव आयोग की ओर से एसआईआर के अंतर्गत की जा रही कार्यवाही में केवल उन्हीं लोगों के नाम हटाए हैं, जिनके हटाए जाना चाहिए। चुनाव आयोग ने जब इन आरोपों को सबूत के साथ लिखित में देने को कहा तो कोई भी सामने नहीं आया। आज विपक्ष की राजनीति लगभग ऐसी ही होती रही है। आरोप लगाने मात्र से कोई अपराधी नहीं बन जाता, उसके लिए समय पर प्रमाण भी देना होता है। ऐसा ही एक निराधार मामला हरियाणा के चुनाव से जुड़ा हुआ है। जिसमें कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा है कि हरियाणा विधानसभा के चुनाव में ब्राजील की एक मॉडल ने 22 बार वोट डाला है। इसके विपरीत मॉडल लारिसा नेरी का कहना है कि वे भारत कभी गई ही नहीं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब वे भारत आई ही नहीं, तब कांग्रेस का यह आरोप केवल एक नैरेटिव स्थापित करने जैसा ही माना जा सकता है। राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं पर इस प्रकार का असत्य आरोप लगाना निश्चित ही लोकतंत्र के लिए घातक ही है। बिहार चुनाव के लिए इस प्रकार के आरोपों में कितना दम है, यह तो जांच करने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या राजनीति में इस प्रकार के आरोप लगाना उचित है। यकीनन इसका उत्तर नहीं ही होगा। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल द्वारा ऐसे आरोप लगाने के यही निहितार्थ निकाले जा सकते हैं कि उनको किसी भी प्रकार से बिहार में अपनी सरकार बनाना है। आज बिहार के प्रमुख राजनीतिक दलों के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, जिसके सहारे जनता को प्रभावित किया जा सके। इसलिए सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाने की राजनीति कर रहे हैं। बिहार के राजनीतिक परिदृश्य की बात की जाए तो वहां भाजपा, कांग्रेस, राजद और जदयू के आसपास ही सत्ता के ताले की चाबी घूमती रहती है। अब भाजपा, जदयू, कांग्रेस, राजद के नेता अपनी पीठ पर तरकश बांधकर तैयार खड़े हैं। किसके तीरों से किसका संधान होगा, यह भविष्य के गर्भ में है। जहां एक ओर राजद की ओर से नीतीश कुमार को राजनीति के लिए अनफिट बताने का प्रयास किया जा रहा है।

शराब की लुभावनी पैकेजिंग के खतरे एवं सुप्रीम कोर्ट की चिंता

हाल ही में देश की शीर्ष अदालत ने शराब की पैकेजिंग को लेकर जो गंभीर टिप्पणी की है, वह केवल कानूनी हस्तक्षेप नहीं बल्कि सामाजिक चेतना को झकझोरने वाली चेतावनी है। अदालत ने स्पष्ट कहा है कि शराब को इस तरह आकर्षक और लुभावना बनाकर प्रस्तुत करना सार्वजनिक स्वास्थ्य के साथ-साथ संस्कृति एवं सामाजिक के साथ खिलवाड़ है। चमकीली बोतलें, विदेशी डिजाइन, चटकदार रंग और ग्लैमरस बॉक्स-ये सब रणनीतियां लोगों को, विशेषकर युवाओं को, महिलाओं को शराब की ओर खींचने का साधन बन चुकी हैं। शराब की यह भ्रामक एवं बाजारवादी पैकेजिंग एक गंभीर एवं नया खतरा है। यह प्रवृत्ति केवल बाज़ार का विस्तार नहीं बल्कि पूरे समाज के स्वास्थ्य, नैतिकता और मानसिक संतुलन पर गहरा हमला है। जन-स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाली शराब कम्पनियों की दुराग्रही सोच एवं गुमराह करने वाली पैकिंग एक आपराधिक कृत्य है। जूस पैक जैसे दिखने वाले टेट्रा पैक में बेची जा रही शराब अनेक खतरों को आमंत्रण है।

आज जब देश शराब की वजह से होने वाली बीमारियों, दुर्घटनाओं, हिंसा, पारिवारिक विघटन और मानसिक अवसाद जैसी समस्याओं से जूझ रहा है, तब शराब को 'फैशनेबल' बनाकर बेचना एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। शराब कंपनियों ने पैकेजिंग को आधुनिकता, प्रतिष्ठा और स्टाइल से जोड़ दिया है, जिससे युवा वर्ग इसे किसी उपलब्धि जैसा मानने लगा है। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रूप से यह पैकेजिंग व्यक्ति के मन में यह भ्रम पैदा करती है कि शराब पीना आधुनिकता का प्रतीक है, जबकि वास्तविकता यह है कि शराब हर रूप में शरीर और मन के लिए घातक ज़हर है। शराब के घातक एवं दुष्प्रभाव किसी से छिपे नहीं हैं। यह धीरे-धीरे शरीर को भीतर से खोखला करते हुए नशे की अंधी गलियों में धकेल देती है। लिवर सिरोसिस, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, कैंसर, मानसिक असंतुलन, अवसाद और नींद की गंभीर समस्याएं शराब सेवन की सीधी देन हैं। सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले हजारों लोग शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण अपनी जान गंवाते हैं। घरेलू हिंसा, अपराध और परिवारों के टूटने में शराब की भूमिका लंबे समय से प्रमाणित है। ऐसे में शराब को आकर्षक पैकेजिंग में परोसना मानो लोगों को स्वेच्छा से विनाश के रास्ते पर भेजने जैसा है।

सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए चिंता जताई है कि शराब की बोतलों की पैकिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए जो उपभोक्ता को उसकी वास्तविक हानियों से दूर ले जाए। चेतावनियां अक्सर बोतल के किनारे इस तरह लगाई जाती हैं कि वे दिखती ही नहीं। कंपनियां स्वास्थ्य चेतावनियों को ढककर अपने उत्पाद की सुंदरता को आगे करती हैं। यह न केवल अनैतिक है बल्कि स्वास्थ्य संबंधी नीतियों की मूल भावना के भी विरुद्ध है। जब सरकार तंबाकू पर बड़ी और भयावह चेतावनियों को अनिवार्य कर चुकी है, तो शराब जिसका स्वास्थ्य पर प्रभाव कई मामलों में उतना ही विनाशकारी है, उसकी पैकेजिंग पर भी समान कठोर नियम लागू होना चाहिए। समाज में शराब की बढ़ती स्वीकृति का बड़ा कारण यह भी है कि शराब उद्योग ने पैकेजिंग को ही आकर्षक विज्ञापन का माध्यम बना दिया है। जहां शराब विज्ञापन पर कानूनी रोक है, वहां कंपनियां रंगीन बोतलों और खूबसूरत बॉक्सों को ही प्रचार का तरीका बना लेती हैं। यह परोक्ष विज्ञापन है, जो कानून की भावना का उल्लंघन करता है और युवाओं को नशे की ओर ले जाता है। ऐसे में सादे, सरल और सामान्य पैकेजिंग की दिशा में कदम बढ़ाना आवश्यक है, ताकि शराब किसी 'लक्ज़री उत्पाद' की तरह न दिखे, बल्कि उसका स्वरूप ही लोगों को चेतावनी देने वाला बने।

यह भी चिंताजनक है कि शराब उद्योग का उद्देश्य केवल बिक्री बढ़ाना है, भले ही उससे समाज कितना भी प्रभावित क्यों न हो। वे यह नहीं देखते कि शराब कितने घर बर्बाद कर रही है, कितने लोग बीमार हो रहे हैं और कितनी जिंदगियां संकट में हैं। इस मानसिकता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई बेहद आवश्यक है। शराब की ग्लैमरस पैकेजिंग पर रोक लगाने से न केवल उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ेगी, बल्कि समाज में नशामुक्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण वातावरण भी बनेगा। सरकारों के लिये राजस्व का बड़ा जरिया शराब है, इसलिये सरकारें भी शराब के खिलाफ खुलकर सामने नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट की इस चेतावनी को केवल उद्योगों के लिए ही नहीं, बल्कि सरकार, समाज और परिवारों के लिए भी महत्वपूर्ण संदेश के रूप में देखा जाना चाहिए। शराब किसी भी रूप में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और उसे आकर्षक बनाकर बेचना मानव जीवन के मूल्य को कम करना है। आज आवश्यकता है कि शराब की पैकेजिंग को नियंत्रित किया जाए, उसे सामान्य और गैर-आकर्षक बनाया जाए, स्पष्ट चेतावनियां लिखी जाएं और शराब को समाज में सम्मानजनक स्थान देने वाली प्रवृत्तियों पर रोक लगे। सरकार को भी स्वस्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ऐसे कानून बनाने चाहिए जो शराब उद्योग की विपणन चालों को सीमित करें।

आज शराब का प्रसार केवल स्वास्थ्य का संकट नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक विघटन का बड़ा कारण बनता जा रहा है। शराब से जुड़े अपराधों और हिंसा की घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि हुई है, विशेषकर महिलाओं के प्रति अत्याचार, घरेलू हिंसा, आर्थिक शोषण और मानसिक प्रताड़ना का बड़ा कारक शराब ही बन रही है। अनेक अध्ययन बताते हैं कि महिलाओं के खिलाफ होने वाली लगभग आधी हिंसक घटनाओं में शराब प्रमुख भूमिका निभाती है। नशे में धुत्त पुरुष अक्सर पारिवारिक तनाव, गुस्से और असंतुलन के कारण महिलाओं पर अत्याचार कर बैठते हैं, जिससे न केवल उनका आत्मसम्मान टूटता है बल्कि पूरा परिवार भय, असुरक्षा और अपमान के वातावरण में जीने को मजबूर हो जाता है। शराब का यह प्रभाव किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं, बल्कि ग्रामीण से शहरी, गरीब से सम्पन्न वर्ग तक फैल चुका है और इसे अनदेखा करना अब समाज के लिए संभव नहीं।

चिंता का विषय यह भी है कि शराब अब केवल बार या नाइट क्लबों तक सीमित नहीं, बल्कि सामाजिक अवसरों-शादियों, जन्मदिनों, दफ्तर की पार्टियों, त्योहारों, यहां तक कि छोटे सामाजिक समारोहों में भी परोसी जाने लगी है। शराब को 'सामाजिकता का हिस्सा' और 'आधुनिकता का प्रतीक' बताकर जिस तरह से उसकी पैठ बढ़ाई जा रही है, वह एक खतरनाक सांस्कृतिक परिवर्तन का संकेत है। परिवारों में युवा पीढ़ी अपने बड़ों को शराब का उपभोग करते हुए देखकर इसे सामान्य मानने लगी है, जिससे किशोर अवस्था में ही शराब सेवन की शुरुआत हो जाती है। स्कूल-कॉलेज के छात्र फैशन, दबाव, दोस्तों की नकल और विज्ञापन जैसी पैकेजिंग के प्रभाव में आकर शराब की लत में डूब रहे हैं। यह पीढ़ी मानसिक एवं शारीरिक दोनों स्तर पर कमजोर होती जा रही है। शराब न केवल उनकी पढ़ाई, कैरियर एवं सोचने-समझने की क्षमता को नष्ट करती है, बल्कि भविष्य के परिवार एवं समाज की नींव तक को हिला देती है। इन बढ़ती चिन्ताओं का समाधान केवल कानून से नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता, सांस्कृतिक पुनर्संयम और परिवारों में जिम्मेदार व्यवहार से ही संभव है।

समाज तभी सुरक्षित हो सकता है जब हम शराब को आकर्षण का नहीं, विनाश का प्रतीक मानें। उसकी पैकेजिंग में चमक-दमक नहीं, चेतावनी झलके। उसका सेवन आधुनिकता नहीं, दुर्बलता समझा जाए। यह चेतना तभी बढ़ेगी जब कानून भी कठोर होंगे और समाज भी सजग।

ललित गर्ग

राजनीति में लैटरल इंट्री

देश में बहुत सी घटनाएं घट रही हैं। चोर दरवाजे से आई ए एस बनाये जा रहे थे, अब मंत्री तक बनाए जा रहे हैं। गोरख पाण्डेय ने सही लिखा था- 'समाजवाद बबुआ धीरे-धीरे आई।' दिल्ली से चलकर समाजवाद पटना आता है। पटना में थोड़ी मौज मस्ती कर लेता है। होटल मौर्या या चाणक्य के बाद जिले की ओर चलता है। जनता तक आते-आते समाजवाद थक जाता है। समाजवाद पर लीडर की उम्र का भी असर पड़ता है। अगर आप डॉ लोहिया की किताब ' भारत विभाजन के गुनहगार' पढ़ें तो पता चलेगा कि उन्होंने भारत विभाजन के कई कारणों में से एक कारण उम्र को भी गिनाया है। नेहरू और पटेल हड़बड़ी में थे। लड़ते लड़ते थक गए थे।

राजगद्दी के लिए कितना इंतजार करते! जिन्ना और लियाकत खान भी मुंह फाड़े हुए थे। एक देश में सभी को तो मुकम्मल जहां नहीं मिलता, सो देश को ही फ़ाड़ दिया। उन

लोगों ने ऐसी-ऐसी थ्योरी दी, लोग हैरत में थे। उन्होंने हिन्दुओं और मुसलमानों को दो राष्ट्र का दर्जा दिया। कहां कि दोनों साथ रह ही नहीं सकते। सावरकर तो उस वक्त न तीन में थे, ना तेरह में। अंग्रेजों के तलवे सहलाकर जीवन गुजार रहे थे। हिन्दुओं के नेता बनने के फिराक में रहते थे। आजादी आंदोलन से उन्होंने तौबा कर लिया था। वे भी दो राष्ट्र का सिद्धांत भांज रहे थे।

मांस, मदिरा सेवन करने वाले जिन्ना ने जीवन में एक पर्चा भी नहीं लिखा। लेकिन भारत विभाजन के प्रमुख गुनहगारों में उनका भी नाम है। देश को रद - बद कर इधर भी पदधारी हुए, उधर भी। सभी एक एक कर गए, लेकिन देश को आग में झोंक कर गए। एक से दो देश निकला, फिर तीसरा निकला। चौथा अभी गर्भ में है। नेताओं की जिह्वा पर गर्म खून की आदत लग जाय तो देश? बचता नहीं है। इन लोगों ने देश को खौलते कराह में डाल दिया है।

खैर, मैं भटक गया था। बात समाजवादियों और उनकी लैटरल इंट्री की बात हो रही थी। डॉ लोहिया ने शादी नहीं की। जयप्रकाश नारायण वादों से बंधे थे। सो दोनों समाजवादी नेता संतान से महरूम रहे। उसके बाद जो समाजवादी आये। वे संतानों से लैस थे। राजनीति में उन्होंने लैटरल इंट्री का रिकॉर्ड बना दिया। पति, पत्नी, बेटा, बेटी, समधी, समधन - सभी देश? की सेवा के लिए न्यौछावर हो गये। जब समाजवाद इस राह पर चल पड़ा तो दक्षिणपंथ क्यों दक्षिण में रहे। उसने भी जम कर अपने पुत्रों और पुत्रियों से देश? की सेवा करवायी। देश इनका कृतज्ञ हैं। वे सेवा किए जा रहे हैं और देश सेवा नहीं ले पा रहा है। देश सेवा के लिए जगह कम है और देश सेवक बहुत हैं। ऐसे देश सेवकों का कहना है कि हमारे लिए देश सेवा परमो धर्मः है। बंदे मातरम गीत गाकर भले क्रांतिकारी शहीद हो गए, मगर परिवारवादी ने जिद ठान ली है कि चाहे जिस पद और जिस तिकड़म से जाना पड़े, वे जायेंगे। मुंह कदापि नहीं मोड़ेंगे। इस स्वर्ण युगीन घटना का नाजुक मोड़ यह है कि एक परिवारवादी दूसरे से सिखते हैं और एक-दूसरे पर तर्क मढ़ कर अपने को गांमा पहलवान बनाते हैं। परिवारवादी समर्थकों की तो मौज ही मौज है। उन्हें परिवारवाद के समर्थन में मुकम्मल तर्क मिल जाता है। वे कहते हैं कि हमारे वाले परिवारवादी हैं तो वे क्या हैं? ऐसे तर्कों से दोनों समृद्ध और संतुलित हो जाते हैं। इस तर्कहीन दुनिया में ऐसे तर्क बहुत काम के होते हैं। आनेवाले समय में आपको ऐसे ऐसे महान तर्कों से मुलाकात होगी। जातिवादी छोकड़े तो ऐसे मौकों पर गजब ढाते हैं। वे उनके स्वागत के लिए नयन बिछाए रहते हैं। लगता है कि इनका जन्म ही स्वागत के लिए हुआ है।

युग प्रभात

खतरे की घंटी : अपराध की राह पर किशोर

हापुड़ (यूपी) में एक किशोर बेटे ने अपने दो दोस्तों की मदद से किसान पिता की गोली मारकर हत्या कर दी और वारदात को आत्महत्या का मामला बता दिया। अब पुलिस जांच में पाया गया है कि पिता का कुसूर इतना था कि इकलौते बेटे की किसी गलती पर पिटाई की थी जिसका अंजाम बेटे ने पिता को खेत पर बुला कर गोली से उड़ा दिया। यह वारदात बता रही है कि समाज में नाबालिग मन मस्तिष्क कितने शातिर ढंग से अपराध कर रहे हैं।

पिछले कुछ माह में राजधानी दिल्ली के मुंडका में नाबालिग की गला रेतकर हत्या। फर्श बाजार में 73 वर्षीय बुजुर्ग की चाकू घोंपकर हत्या। आनंद पर्वत में बदले के लिए युवक की हत्या। जहांगीरपुरी में वर्चस्व कायम करने के लिए युवक की हत्या। इन सभी हत्याओं का जिक्र कर रहे हैं, इन सभी को 14 से 17 साल के बीच के नाबालिग लड़कों ने अंजाम दिया। जिस उम्र में कंधे पर बस्ता और हाथों में कलम होना चाहिए, उसी उम्र में नाबालिग अपराध की दुनिया का रुख कर रहे हैं। इसके पीछे कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन पुलिस के लिए यह नाबालिग मुसीबत बन गए हैं।

पढ़ने की उम्र में नाबालिग अपराध की दुनिया में कदम बढ़ा रहे हैं। चोरी, लूटपाट ही नहीं, लोगों का खून बहा रहे हैं।सगे संबंधी पडोसी और परिचित के साथ भी वारदात करने में उनको जरा भी हिचक नहीं हो रही। कई नाबालिग अपराधी तो ऐसे हैं, जो बाल सुधार गृह जाकर भी नहीं सुधर रहे। वह वहां से बाहर आने के बाद अपराध के क्षेत्र में फिर से सक्रिय हो रहे हैं।

बीते दिनों दिल्ली के विजय विहार इलाके में लूट का विरोध करने वाले एक ऑटो चालक की निर्मम हत्या में पांच नाबालिगों की गिरफ्तारी गंभीर चिंता बढ़ाने वाली है। देश में नाबालिगों के बालिगों की तर्ज पर गंभीर

अपराधों को अंजाम देने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। वहीं दिल्ली की घटना में गिरफ्तार किशोरों की स्वीकारोक्ति डराने वाली है कि वे नशे के आदी हैं और पैसे जुटाने के लिये लूटपाट जैसे अपराधों में लिप्त रहते हैं। यह घटना हमारे समाज में पनप रही विकृतियों की ओर इशारा कर रही है

सीलमपुर में 13 वर्षीय करण की हत्या इसका स्पष्ट उदाहरण है। यह समाज के लिए चिंता की बात है। जघन्य अपराधों में संलिप्त नाबालिगों को लेकर कानून लचर होने के कारण यह दुस्साहस बढ़ रहा है। नाबालिग अपराधियों के हाथों जिनके अपने मारे गए, वह कानून में बदलाव के जरिये सख्ती करने की मांग कर रहे हैं।

जाफराबाद में 11 जुलाई 2024 को भाई व दोस्त के साथ कपड़े खरीद रहे 15 वर्षीय मोहम्मद फैज की दुकान से बाहर निकाल बीच बाजार में गोली मार कर हत्या कर दी थी। इस वारदात को नाबालिग शमिल था। उसे पुलिस ने पकड़ कर बाल सुधार गृह भेजा था। अब वह बाहर है। बालिग हो चुका है और हाल में उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने उसे एक अन्य अपराध के मामले में गिरफ्तार किया है।

आरोपित गैंग्स्टर बन चुका है। मृतक के पिता मोहम्मद गुफरान का कहना है कि यह न्यायोचित नहीं है कि हत्या जैसा गंभीर अपराध करने वाले को इस बात पर रहम दे दिया जाए कि वह नाबालिग है।

न्यू सीलमुर के 17 वर्षीय कुणाल की इसी वर्ष 17 अप्रैल को हत्या कर दी गई थी। इस वारदात में दो नाबालिग शामिल थे, जिन्हें पुलिस ने पकड़ा था। कुछ ही महीनों में वह बाल सुधार गृह से बाहर आ गए। अब वह खुली हवा में सांस ले रहे हैं।यह स्थिति देख कर कुणाल के स्वजन का दम घुट रहा है। उसकी मां प्रवीन अब न्याय की उम्मीद छोड़ चुकी हैं।

अब वक्त आ गया है कि किशोर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिये सख्त कानूनों के प्रावधान हों। इसकी वजह यह है कि किशोरों को अपराध करने के बाद सामान्य जेलों में रखने के बजाय बाल सुधार गृहों में भेज दिया जाता है। लेकिन बाल सुधार गृहों में रहने के दौरान भी ऐसे अपराधी किशोरों में बड़ा बदलाव नजर नहीं आता। अक्सर देखा जाता है कि बाल सुधार गृहों में रहने की सीमित अवधि के बाद कई किशोर फिर अपराधों की दुनिया में उतर जाते हैं। समाज विज्ञानियों का मानना है कि किशोर अपराधों को लेकर कानून के अस्पष्ट और लचर होने की वजह से भी दोषियों को दंडित नहीं किया जा सकता। अक्सर कहा जाता है कि नाबालिगों की सजा के मामले में अभियुक्त की उम्र को घटा दिया जाए। दरअसल, बदलते परिवेश में समय से पहले किशोरों में वयस्कों की नकारात्मक प्रवृत्तियां पनपने लगी हैं। जिसके चलते वे बड़ों के जैसे अपराध तो करते हैं। लेकिन उन्हें उस अनुपात में सजा नहीं दी जा सकती। वैसे यह भी हकीकत है कि किशोरों के सामने लंबा भविष्य होता है। यदि परिस्थितिवश या मजबूरी में वे कोई अपराध करते हैं तो उन्हें सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए। वैसे भी दंड का अंतिम उद्देश्य व्यक्ति में सुधार ही होता है। किशोर सजा काटने के बाद भी लगातार अपराध की दुनिया में सक्रिय रहते हैं तो उसके लिये दंड के सख्त प्रावधान होने चाहिए। वहीं, अपराध के मूल में आर्थिक विषमताएं भी हैं, जिसके चलते वे पढ़-लिख नहीं पाते हैं। लेकिन हाल के वर्षों में तमाम सामाजिक विद्रूपताएं भी किशोर मन में नकारात्मक प्रभाव डाल रही हैं। जैसेकि दिल्ली की घटना में लिप्त किशोरों ने स्वीकारा कि वे नशे के आदी हैं,

यह घटना हमारे समाज में नशे के नासूर से उपजे संकट की ओर इशारा करती है। ऐसे में नशे पर अंकुश के साथ ही उन सामाजिक विसंगतियों पर नजर रखने की जरूरत है जो किशोर मन के भटकाव को जन्म देती हैं। भारतीय समाज में जीवन मूल्यों का तेजी से होता पतन भी एक वजह है। किशोरों को नैतिक शिक्षा का पाठ सही ढंग से न स्कूलों में मिल पा रहा है और न ही घरों में। इस संकट का एक बड़ा पहलू इंटरनेट पर जहरीली व अश्लील सामग्री की प्रचुरता भी है। अक्सर किशोरों द्वारा भी इंटरनेट पर अश्लील सामग्री देखने के बाद यौन हिंसा को अंजाम दिया जाता है । ऐसे में बच्चों को संस्कार स्कूल और घर के बजाय मोबाइल से मिल रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि सोशल मीडिया व इंटरनेट से जुड़े विभिन्न माध्यमों में परोसी जा रही विषैली सामग्री बाल मन पर बुरा असर डाल रही है। ऐसे में नशा, अश्लीलता और अपराध उन्मुख कार्यक्रम किशोरों को अपराध की गलियों में गुजरने के लिए उकसा रहे हैं। बहरहाल, अब समय आ गया है कि नीति-नियंताओं को विचार करना चाहिए कि हत्या-बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में लिप्त किशोरों के लिये कैसे कानून बनें। निश्चय ही कानून का मकसद किसी अपराधी में सुधार ही होना चाहिए। लेकिन इस छूट को सजा से छूट का हथियार बनने देने से भी रोकना चाहिए। कानून में समय परिस्थितियों की मांग के अनुसार परिवर्तन और सुधार करने की जरूरत है अब ऐसे गिरोह भी सक्रिय हैं जो नाबालिगो को कच्चा लालच देकर हायर कर संगीन वारदातों को साजिशन अंजाम दिला रहे हैं। बड़े गैंगस्टर भी इनको वारदातों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल करते हैं।

कुछ साल पहले चार नाबालिग लड़कों ने कड़कड़डूमा कोर्ट में जज के कमरे में घुसकर गैंगस्टर इरफान उर्फ छेनू पर हमला करवा दिया था। इन लोगों ने छेनू को पांच गोली मारी, लेकिन उसके बाद भी वह जिंदा बच गया। हमले में दिल्ली पुलिस का एक हवलदार इन नाबालिगों की गोली लगने से मारा गया था। बाद में पता चला था कि छेनू के विरोधी नासिर ने इन नाबालिग शूटरों का इंतजाम किया था। इसके बाद से लगातार इन नाबालिगों के इस्तेमाल का तेजी से ट्रेंड बढ़ गया। मौजूदा समय में बदमाश लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि नाबालिगो की परवरिश के लिए समाज में स्वस्थ माहौल की स्थापना की जाए उनके भीतर नैतिकता रोपी जाए ताकि बचपन भविष्य का अपराधी बनने से बचाया जा सके।

सुप्रीम कोर्ट की राय से बेलगाम होंगे राज्यपाल?

20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए संवैधानिक सवालों पर अपनी राय देते हुए यह स्पष्ट कर दिया है, कि राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर निर्णय लेने की कोई समय-सीमा तय नहीं की जा सकती है। अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की खंडपीठ ने तीन महीने की अनिवार्य समय-सीमा तय की थी। जिससे विपक्षी राज्यों की सरकारों को उम्मीद बंधी थी, कि केंद्र सरकार के इशारे पर राज्यपालों द्वारा विधेयक रोकने की जो राजनीति की जा रही थी, वह अब खत्म होगी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में हुई सुनवाई के बाद दो जजों की खंडपीठ का फैसला अब विवादों में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट की राय दो जजों वाली खंडपीठ के फैसले के विपरीत है। यहीं से एक बड़ी कानूनी और राजनीतिक बहस शुरू होती है। सुप्रीम कोर्ट की इस राय से एक बार फिर राज्यपालों की शक्तियों को फिर से अनियंत्रित ताकत मिल गई है। इस ताकत मिलने के बाद क्या राज्यपाल ही राज्य के असली संवैधानिक मुखिया होंगे? दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में सारे देश ने यह देख लिया है, कि उपराज्यपाल निर्वाचित सरकार के ऊपर भारी पड़े। जो उपराज्यपाल चाहते थे वही काम दिल्ली सरकार को करने पड़े। भारत की संघीय लोकतांत्रिक संरचना तभी संतुलित रह सकती है जब केंद्र और राज्य दोनों संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करें। एक-दूसरे के अधिकारों पर हस्तक्षेप ना करें। पिछले वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा राज्यपालों के माध्यम से विपक्षी राज्यों की सरकार और वहां की विधानसभा पर अघोषित रूप से अधिकार में लेने की जो कोशिश की जा रही थी सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से राज्यपाल विधेयकों को मंजूरी देने में अब बिना किसी भय के राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के इशारे पर परेशान करेंगे बिना कारण बताये। दिल्ली, तमिलनाडु, केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल इसके उदाहरण हैं। जहां सरकारों को अपने ही राज्य की विधानसभा और निर्वाचित विधायकों द्वारा जो कानून बनाए गए थे उन्हें लागू कराने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। यही कारण था सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल वाले आदेश से उम्मीद जगी थी। केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच संस्थागत टकराव कम होगा। राज्यपालों की भूमिका स्पष्ट होगी। राज्य सरकार और राज्यपाल अपनी-अपनी भूमिका में काम करेंगे। 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने जो राय दी है, उसने स्थिति को एक बार फिर धुंधला बना दिया है। अदालत ने कहा है समय सीमा थोपने से न्यायपालिका, कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करेगी। जो संविधान के प्रावधान हैं उनके खिलाफ है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, कि राज्यपाल अनिश्चितकाल तक विधेयक लंबित नहीं रख सकते हैं। यदि देरी बिना कारण हो, तो अदालत सीमित दायरे में रहकर हस्तक्षेप कर सकती है। यही अनिश्चितता इस मामले को और जटिल बनाता है। राज्यपाल कब तक इंतजार करवा सकते हैं? अनिश्चितकाल नहीं का व्यावहारिक अर्थ क्या है? क्या फिर से हर राज्य को देरी होने पर कोर्ट जाना पड़ेगा? सबसे बड़ा खतरा यही है, यह अस्पष्टता राजनीतिक लाभ लेने वालों के लिए नया अवसर खोलती है। केंद्र सरकार के पास राज्यों से कई गुना ज्यादा अधिकार हैं। केंद्र सरकार राज्यपालों की नियुक्ति करती है। राज्यपाल एक संवैधानिक अधिकारी हैं। राजनीतिक निष्ठा के चलते राज्यपाल के पद पर ऐसे लोगों को नियुक्त किया जाता है जो किसी विशेष विचारधारा तथा किसी विशेष संगठन के रूप में कार्य करते हैं। राज्यपालों के उपर विवेकाधीन-शक्ति बिना समय-सीमा तथा बिना जिम्मेदारी के छोड़ दी जाती है। ऐसी स्थिति में विपक्ष-शासित राज्यों में विधायी प्रक्रिया को रोककर केंद्र में जो राजनीतिक दल बैठा है वह राज्यों में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए इस तरह की कार्रवाई को बढ़ावा देगा। संघीय ढांचे में केंद्र सरकार की अलग शक्तियां हैं तथा राज्य सरकारों को उनके राज्य के लिए अलग शक्तियां प्राप्त हैं। चुनी हुई सरकारों की शक्ति कानून बनाने और कानून का पालन कराने में निहित है। यदि राज्यपाल राजनीतिक कारणों से इस प्रक्रिया को महीनों, वर्षों तक रोक कर रखते हैं तब यह संविधान एवं लोकतांत्रिक जनादेश का घोर अपमान है।

सवाल यह है, केंद्र एवं राज्यों में अलग-अलग दलों की सरकारें हैं। मतदाताओं की केंद्र के लिए अलग दृष्टि है और राज्य के लिए अलग दृष्टि है। वह मतदान के जरिए अपनी राय व्यक्त करता है और अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करता है। सवाल यह है, क्या राज्य सरकारें अपना वैधानिक काम अपने राज्य के मतदाताओं के लिए समय पर कर पाएंगी या वह लगातार अदालतों के चक्कर काटती रहेंगी? सुप्रीम कोर्ट की राय ने एक खिड़की खोली है और एक खिड़की को बंद भी कर दिया है। अधखुली खिड़की से भारत की संघीय व्यवस्था में ठंडी हवा नहीं, बल्कि एक नया राजनीतिक तूफान आना तय है। यह तूफान दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार और उपराज्यपाल के बीच में पहले ही देखने को मिल चुका है। अब यह सारे देश में देखने को मिलेगा। यह आशंका बन गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो राय राष्ट्रपति को भेजी है उसके बाद केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच एक नई बहस और सत्ता संतुलन के लिए नया संघर्ष शुरू होगा। राज्यपालों को जवाबदेह बनाए बिना देश का संघीय ढांचा सुरक्षित नहीं रह सकता। राज्यपालों के जरिए केंद्र सरकार द्वारा राज्यों की सत्ता पर नियंत्रण करने का जो काम पिछले 10 वर्षों से कर रही थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो राय व्यक्त की गई है उसके बाद देश में अधिकारों को लेकर एक नया संघर्ष केंद्र एवं राज्यों के बीच बनना तय है। भारत में अभी तक जो संघीय व्यवस्था चल रही थी, अब उसमें टकराव बढ़ना तय है। दक्षिण के राज्य पहले भी इस तरह के टकराव के बारे में अपने बयान दे चुके हैं। पश्चिम बंगाल में पिछले 10 साल से राज्यपालों की जो भूमिका रही है उसके बाद पूर्वोत्तर के राज्यों में भी इसी तरह से टकराव सामने आ सकता है। यह स्थिति कहीं से कहीं तक अच्छी नहीं मानी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सभी राज्यों और केंद्र की राय सुनवाई करने के बाद जो राय दी है वह आधी-अधूरी है। इससे केंद्र एवं राज्यों के संबंध और भी ज्यादा खराब होंगे। न्यायपालिका ने दो बंदरों की लड़ाई में अपने आप को एक ऐसी भूमिका में रख लिया है जो समय-समय पर इस तरह के निर्णय दे जिससे न्यायपालिका अपने आप को भी सुरक्षित रख पाए। इस राय से यही प्रतीत हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीश सरकार के दबाव में हैं। सरकार का न्यायपालिका पर हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। इस तरह के आरोप पिछले वर्षों में कई बार लग चुके हैं। पहले भी जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आए हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो मामले कई वर्षों से लंबित हैं और सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में जिस तरह से मामलों को तारीख पर तारीख देकर टाला जाता है। महाराष्ट्र की सरकार जिस तरह से राज्यपाल के हस्तक्षेप से गिरा दी गई थी, उस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने अस्वैधानिक बताया था। उसके बाद भी उस सरकार ने अपना पूरा कार्यकाल किया। राज्यपाल के ऊपर असंवैधानिक काम करने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

- सनत जैन

अंतरराष्ट्रीय संबंधों के यथार्थवादी सिद्धांत के अनुसार, हर देश का सर्वोच्च उद्देश्य अपनी सुरक्षा, शक्ति और हितों की रक्षा करना होता है

वैश्विक स्तरपर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के बीच 19 नवंबर 2025 को चल रही गलबहियां पूरी दुनियाँ ने देखी अमेरिकी राष्ट्रपति ने सऊदी को प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी बता दिया है और एफ़-35, परमाणु डील समेत कई महान समझौते किए हैं मध्य -पूर्व की राजनीति में खलबली मचा देने वाले इन दो देशों ने 1945 में भी एक महान समझौता किया था,जब एक युद्धपोत पर राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और आधुनिक सऊदी किंग अब्दुलअजीज इब्न सऊद की मुलाकात हुई थी,इसी मुलाकात के बाद क्विंसी समझौते की नींव रखी गई थी।वैश्विक राजनीति सदियों से राष्ट्रीय स्वार्थ और रणनीतिक लाभ के सिद्धांत पर संचालित होती रही है।चाहे वह साम्राज्य वाद के दौर कीविस्तारवादी नीतियाँ हों, शीतयुद्ध काल के दो ध्रुवीय गठबंधन, या 21वीं सदी की आर्थिक-रणनीतिक कूटनीति, हर युग में महाशक्तियों ने अपनी प्राथमिकताओं को सर्वोपरि रखा। अभी हाल ही में एक दिन पूर्व डोनाल्ड ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान (एमबीएस) के बीच हुए ऐतिहासिक समझौतों निवेश के वायदों को भी इसी रूप में देखा जा सकता है। इन दोनों के बीच एक दिन पूरा वाइट हाउसमें जो हुआ वह सिद्धांत को पुष्ट करती हैं कि राजनीति में स्थायी कुछ नहीं होता, केवल राष्ट्रीय हित स्थायी होते हैं।यह लेख इन दोनों नेताओं के हालिया व्हाइट हाउस संवाद,उससे जुड़े रणनीतिक व्यापारिक और सैन्य समझौतों तथा वैश्विक शक्ति समीकरणों पर पड़े प्रभाव का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है।मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि राजनीति में स्वार्थ की अवधारणा नई नहीं है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों केयथार्थवादी सिद्धांत के अनुसार, हर देश का सर्वोच्च उद्देश्य अपनी सुरक्षा, शक्ति और हितों की रक्षा करना होता है। यह सिद्धांत बताता है कि कोई भी राष्ट्र,चाहे वह अमेरिका हो, सऊदी अरब हो या भारत,वैश्विक मंच पर उन्हीं निर्णयों को प्राथमिकता देता है,जिनसे उसका सामरिक, आर्थिक या राजनीतिक हित सुरक्षित रहेडोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट और एमबीएस का विज़न 2030 इसी स्वार्थ- प्रधान रणनीति के दो उदाहरण हैं। दोनों नेता इस धारणा पर चलते हैं कि बड़े फैसलेभावनाओं या सामूहिक नैतिकता के आधार पर नहीं,बल्कि कच्ची वास्तविकताओं, पैसा, सुरक्षा, निवेश, तेल, हथियार और वैश्विक प्रभाव के आधार पर लिए जाते हैं।

साथियों बात अगर हम ट्रंप और एमबीएसः-दो आक्रामक नेताओं की समान नीति-शैली कोसमझने की करें तो डोनाल्ड ट्रंप वैश्विक राजनीति में अपनी लेन-देन आधारित कूटनीति (ट्रांसक्शनल डिप्लोमासी) के लिए जाने जाते हैं। उनके शासनकाल में वैश्विक समझौते लाभ-हानि के कठोर आकलन पर आधारित थे। वे अंतरराष्ट्रीय गठबंधनों पर पुनर्विचार करने,नाटो देशों से अधिक धन मांगने,चीन पर टैरिफ लगाने और पुराने समझौतों को रद्द करने में संकोच नहीं करते थे।इसी प्रकार मोहम्मद बिनसलमान अपने देश को आधुनिक आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए उग्र सुधारवादी नीति अपनाते हैं। सऊदी की तेल-निर्भर अर्थव्यवस्था को विविध बनाने, बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश लाने और मध्य-पूर्व की शक्ति-संतुलन में वर्चस्व बनाए रखने के लिए वे साहसिक कदम उठाते रहे हैं। उनके शासनकाल में सऊदी अरब ने क्षेत्रीय राजनीति में आक्रामक सैन्य और आर्थिक हस्तक्षेपों के माध्यम से खुद को एक निर्णायक शक्ति के रूप में स्थापित किया है।दोनों नेताओं में तीन महत्वपूर्ण समानताएँदिखाई देती हैं(1)राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत (2) आक्रामक कूटनीति(3)बड़े आर्थिक और रक्षा सौदों पर जोर

साथियों बात अगर हम ट्रंप- एमबीएस व्हाइट हाउस बैठकः भू-राजनीतिक हलचल का केंद्र इसको समझने की करें तो, 2018 के बाद पहली बार एमबीएस का अमेरिका आगमन और व्हाइट हाउस में ट्रंप द्वारा किया गया ऐतिहासिक स्वागत वैश्विक मीडिया का केंद्र बन गया यह केवल एक कूटनीतिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि वैश्विक शक्ति समीकरणों को पुनर्परिभाषित करने वाला क्षण था।इस मुलाकात के कई अर्थ थे- (1)सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्तों में आई ठंडक अब समाप्त हो रही है।(2) बाइडेन प्रशासन के तहत मौजूद तनाव और अविश्वास अब इतिहास बनता दिख रहा है।(3) मध्य-पूर्व में अमेरिका अपनी प्रासंगिकता पुनः स्थापित करने की कोशिश कर रहा है।(4) एमबीएस की अंतरराष्ट्रीय छवि, जो खशोगी प्रकरण से धूमिल हुई थी, ट्रंप ने उसे पुनः वैधता प्रदान कर दी।ट्रंप के इस कदम को विश्लेषक व्यवहारिक कूटनीति कहते हैं,जहाँ मानवीय अधिकारों का मुद्दा पीछे छूट जाता है और व्यापार, हथियार सौदे तथा रणनीतिक प्रभाव प्राथमिकता बन जाते हैं।

साथियों बातें कर हम सऊदी को मेजर नॉन-नाटो एली का दर्जा और अभूतपूर्व रक्षा सौदे इसको समझने की करें तो इस बैठक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय था सऊदी अरब को मेजर नॉन-नाटो एली का दर्जा देना।यह दर्जा सामान्यतः उन देशों को मिलता है जो अमेरिका के दीर्घकालिक रक्षा-सहयोगी होते हैं। इससे सऊदी को अमेरिकी तकनीक, हथियार, रक्षा सहयोग, खुफिया सूचना और सुरक्षा साझेदारी के विशेष अधिकार प्राप्त होंगे।यह कदम मध्य-पूर्व में शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल देगा।इसके साथ ही दो बड़े रक्षा समझौते घोषित हुए(1) 48 एफ़-35 स्टील्थ फाइटर जेट की बिक्री-एफ़ -35 दुनिया का सबसे खतरनाक और अत्याधुनिक स्टील्थ विमान है।सऊदी के लिए यह एक गेम-चेंजर सिद्ध होगा।यह इज़रायल, ईरान और तुर्किये जैसे देशों के सैन्य समीकरणों पर गहरा असर डालेगा। (2) 300 अब्राम्स टैंक की बिक्री-अब्राम्स एम 1ए 2 टैंक दुनिया की सबसे उन्नत स्थलीय युद्ध मशीनों में गिना जाता है।इससे सऊदी की थलसेना का सामरिक शक्ति-संतुलन कई गुना बढ़ जाएगा।इन दोनों सौदों के पीछे ट्रंप का साफ संदेश है-बिजनेस इज़ बिजनेस, और अमेरिका का हित सर्वोपरि है।

साथियों बात अगर हम सऊदी का अमेरिका में ऐतिहासिक निवेश,एक ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य इसको समझने की करें तो,एमबीएस ने अमेरिका में सऊदी अरब के निवेश को बढ़ाकर 1 ट्रिलियन डॉलर करने की घोषणा करके वैश्विकआर्थिक जगत में हलचल मचा दी। यह रकम पहले से घोषित 600 अरब डॉलर के निवेश से कहीं अधिक है। उन्होंने अमेरिका को दुनिया का सबसे आकर्षक निवेश गंतव्य बताया, जो स्पष्ट करता है कि सऊदी आर्थिक रूप से अमेरिका पर भरोसा बढ़ा रहा है। यह निवेश केवल आर्थिक नहीं, बल्कि 3 बड़े रणनीतिक उद्देश्यों को साधता है (1) अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सऊदी की निर्णायक भागीदारी(2)द्विपक्षीय संबंधों को वित्तीय आधार पर मजबूती (3) ट्रंप प्रशासन को समर्थन और सुरक्षा गारंटी प्राप्त करना,एफ़ -35 और 300 अब्राम्स टैंकों के अतिरिक्त सऊदी द्वारा 88 लाख करोड़ (अरबों डॉलर) की डील अमेरिकी उद्योग के लिए बड़ी आर्थिक संजीवनी है।ट्रंप के लिए यह बैठक केवल एक कूटनीतिक सफलता नहीं, बल्कि आर्थिक उपलब्धि भी थी,जो एनपीएस (नेशनल परोसपेरिटी सम्मिट) और आगामी चुनावों में उनकी छवि मजबूत करेगी।

साथियों बात अगर हम जमाल खशोगी हत्या मामलाः ट्रंप की क्लीन चिट और विश्व राजनीति में नैतिकता बनाम हितों का संघर्ष इसको समझने की करें तो,2018 में तुर्किये में पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या ने विश्व समुदाय में सऊदी अरब की छवि को गंभीर क्षति पहुंचाई थी। सीआईए ने अपने निष्कर्षों में स्पष्ट रूप से कहा था कि इस हत्या के पीछे सऊदी शासन और एमबीएस की मंजूरी का संदेह है।बाइडेन प्रशासन इसी आधार पर एमबीएस से दूरी बनाए हुए था।परन्तु ट्रंप ने इस बैठक में एमबीएस को क्लीन चिट प्रदान करते हुए कहा कि उन्हें इस मामले में कोई जानकारी नहीं है।यह बयानरणनीतिक और आर्थिक हितों के अनुसार था, राजनीतिक नैतिकता के नहीं।यह कदम यह सिद्ध करता है कि (1) राजनीति में मानवीय अधिकारों से बड़ा राष्ट्रीय हित होता है (2) हथियार, निवेश और भू- रणनीतिक सहयोग नैतिकता से अधिक शक्तिशाली हैं (3) अमेरिका -सऊदी संबंध व्यवहारिकता पर आधारित हैं, न कि आदर्शवाद पर ट्रंप का यह निर्णय आलोचकों की दृष्टि में विवादास्पद है, परन्तु समर्थकों के अनुसार यह राष्ट्रहित आधारित वास्तविक कूटनीति है।

साथियों बात अगर हम इसके अंतरराष्ट्रीय प्रभावः-यहसाझेदारी वैश्विक भू-राजनीति को कैसे बदलेगी? इसको समझने की करें तो ट्रंप,एमबीएस बैठक का वैश्विक परिदृश्य पर प्रभाव अत्यन्त व्यापक है,(1)मध्य-पूर्व का शक्ति-संतुलन बदल जाएगा-एफ़ -35 और अब्राम्स टैंक सऊदी को क्षेत्रीय सुपर- पावर बना देंगे।ईरान के लिए यह गंभीर चुनौती होगी।(2)चीन और रूस पर अप्रत्यक्ष दबाव बढ़ेगा- सऊदी का अमेरिका की ओर झुकाव ऊर्जा और निवेश उद्योग में दोनों देशों के लिए झटका है (3) इज़रायल -सऊदी संबंधों में नई संभावनाएँ-अमेरिका की मध्यस्थता से अब्राहम समझौते 2.0 की राह खुल सकती है।(4)भारत सहित एशिया में कच्चे तेल की राजनीति प्रभावित होगी-सऊदी,अमेरिका गठजोड़ तेल मूल्यों और ऊर्जा आपूर्ति पर असर डालेगा। (5) अमेरिका मध्य-पूर्व में अपनी सैन्यमौजूदगी दोबारा मजबूत करेगा,यह चीन की बेल्ट एंड रोड रणनीति पर भी प्रभाव डालेगा।

अतः अगर हम उपयोग पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि स्वार्थ, रणनीति और शक्ति,21वीं सदी की नई कूटनीति,ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात केवल एक राजनयिक घटना नहीं थी, बल्कि 21वीं सदी की नई भू-राजनीति का स्पष्ट संदेश थी,राष्ट्रहित सर्वोपरि है।इस साझेदारी में अर्थव्यवस्था है,हथियार हैं,निवेश है,रणनीतिक दबाव है,क्षेत्रीय वर्चस्व है,और सबसे महत्वपूर्ण,एक ऐसा गठबंधन है जो आने वाले दशक में विश्व की शक्ति-संरचना को नया स्वरूप दे सकता है।नैतिकता मानवाधिकार, लोकतंत्र जैसे आदर्शों का स्थान यथार्थवादी शक्ति- राजनीति ने फिर से ले लिया है। स्वार्थ-प्रधान राजनीति आज भी वही है,केवल उसके स्वरूप और साधन बदल गए हैं।डोनाल्ड ट्रंप और एमबीएस इस नई विश्व-व्यवस्था के प्रतिनिधि हैं, जहाँ कूटनीति अब केवल संवाद नहीं, बल्कि शक्ति, धन और राष्ट्रीय हितों की प्रतिस्पर्धा है।

किशन सनमुखदास भावनानी

लोगों को वोटर लिस्ट से नाम हटने का डर बोले- हम कम पढ़े-लिखे, फॉर्म का पता नहीं

●नई दिल्ली/भोपाल/रायपुर/जयपुर।

देश के 12 राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण चल रहा है लेकिन चुनाव आयोग ने एसआईआर के लिए जो प्रावधान कर रखा है उसने राजनीतिक पार्टियों, बीएलओ और मतदाताओं को परेशानी में डाल दिया है। खासकर नौकरी, कारोबार, मजदूरी के लिए दूसरे राज्यों में रह रहे प्रवासियों को सबसे अधिक डर सता रहा है। अधिकांश लोगों का कहना है कि उनके गांव से फोन आ रहा है कि जल्दी से फॉर्म भरने आ जाओ, नहीं तो वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा...यहां वोटर लिस्ट अपडेट हो रही है। लाखों प्रवासी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया के दौरान असमंजस के दौर से गुजर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर राजनीति गरमा गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने दावा किया है कि प्रदेश के 80 मतदान केंद्रों में 100 प्रतिशत मतदाता फॉर्म का डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है लेकिन आयोग के इस दावे पर अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधे सवाल खड़े कर दिए हैं।

गौरतलब है कि एसआईआर के मामले में लक्षद्वीप (88.20 प्रतिशत), गोवा (69.38 प्रतिशत), और राजस्थान (65.52 प्रतिशत) से हुआ है। पांच करोड़ से अधिक मतदाताओं वाले राज्यों में, मध्य प्रदेश केवल राजस्थान से पीछे है, जिससे यह प्रभावी रूप से दूसरी स्थिति में है। 4 दिसंबर तक सभी को फॉर्म भरकर जमा करवाना है, ताकि वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटे। लेकिन कई प्रवासियों को इस प्रक्रिया की जानकारी तक नहीं है। कारोबार और नौकरियों के चलते लाखों प्रवासी राज्य के बाहर रहते हैं। ज्यादातर अब तक अपने राज्य में ही वोट डालने आते रहे हैं, लेकिन कुछ प्रवासियों ने बीएलओ को एसआईआर फॉर्म जमा करवाने से मना कर दिया है। ऐसे में अनुमान है कि देश में सबसे ज्यादा वोट प्रवासियों के कम हो सकते हैं। कुछ अभी तक यह तय नहीं कर पा रहे कि उन्हें अपने मूल राज्य में वोट रखना है या जहां वे नौकरी कर रहे हैं।

मध्य प्रदेश में चुनावी मतदाता सूची के डिजिटलीकरण का काम 57.05 प्रतिशत पूरा हो गया है, जिससे यह इस काम में लगे 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चौथे स्थान पर आ गया है। यह प्रगति ऐसे समय में हुई है जब ड्यूटी पर तैनात बूथ-लेवल ऑफिसर्स की मौतें चिंता का विषय बन गई हैं। 11 नवंबर से अब तक कम से कम चार बीएलओ की मौत हो चुकी है, जिनमें से सभी सरकारी स्कूल शिक्षक थे। उनके रिश्तेदारों का आरोप है कि काम का अत्यधिक दबाव, लंबे काम के घंटे और लक्ष्य पूरा न करने पर निलंबन का डर इन मौतों का कारण बना है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, राज्य में 5.73 करोड़ मतदाताओं को 65,014 बीएलओ द्वारा मतदाता सूची में नाम जोडऩे के लिए फॉर्म दिए गए हैं। 23 नवंबर तक इनमें से 3.27 करोड़ फॉर्म डिजिटाइज किए जा चुके थे। इस बीच, बीएलओ की मौतें चिंता बढ़ा रही हैं।

नौसेना में स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस माहे शामिल

मुंबई। स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस माहे सोमवार को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया। यह माहे-क्लास का पहला पनडुब्बी रोधी (एंटी सबमरीन) और उथले पानी (जहां पानी की गहराई कम हो) में चलने वाला युद्धपोत है, जो तटीय इलाकों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। मुंबई में हुए समारोह में आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी मुख्य अतिथि रहे। द्विवेदी ने तीनों सेनाओं की संयुक्त ताकत पर जोर दिया। उन्होंने कहा- सशस्त्र बलों की सबसे बड़ी शक्ति सिनर्जी है। ऑपरेशन सिंदूर इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह जहाज उथले पानी में ऑपरेशन, तटीय इलाकों में गश्त, समुद्री रास्तों की सुरक्षा और दुश्मन पनडुब्बियों की तलाश जैसे कामों में बड़ी भूमिका निभाएगा। ये काम बिना शोर के करने की काबिलियत के चलते इसे 'साइलेंट हंटर' नाम दिया गया है।

युग प्रभात

बिहार विधान सभा चुनाव दे रहे हैं कुछ संकेत

हाल ही में सम्पन्न हुए बिहार राज्य की विधान सभा के चुनाव परिणाम आ गए हैं एवं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन को अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई है। कुल 243 विधायकों में से एनडीए गठबंधन के 202 प्रत्याशी चुनाव जीत कर विधायक बन गए हैं। विधान सभा स्तर के किसी भी चुनाव में सामान्यतः राज्य स्तर की स्थानीय समस्याओं को ध्यान में रखकर ही राज्य के नागरिक अपना वोट देते हैं। परंतु, हाल ही के समय में कई राज्यों के चुनावों में स्थानीय नागरिकों के बीच यह प्रवृत्ति घर करती जा रही है कि जो राष्ट्रीय अथवा स्थानीय दल उन्हें मुफ्त की आकर्षक योजनाएं प्रस्तुत कर रिझाने का प्रयास करता है, उस दल को उस राज्य में अधिक सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस प्रवृत्ति का स्पष्ट संकेत दिल्ली राज्य में वर्ष 2013 में सम्पन्न हुए राज्य विधानसभा के चुनावों में, केवल एक वर्ष पूर्व गठित नए दल, आम आदमी पार्टी के इस विधान सभा चुनाव में 28 सीटों की जीत पर दिखाई दिया था। उस समय आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के समर्थन से अपनी सरकार बनाई थी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली निवासियों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का वायदा इन चुनावों के दौरान किया था, जिसे बाद में पूरा भी किया गया था। इसके बाद तो दिल्ली विधान सभा चुनाव में वर्ष 2025 तक आम आदमी पार्टी का ही लगभग पूर्ण कब्जा रहा, क्योंकि मुफ्त में प्रदान की जाने वाली इसी प्रकार की कुछ और घोषणाओं को भी आम आदमी पार्टी समय समय पर लागू करती रही और दिल्ली के पढ़े लिखे नागरिकों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रही। हालांकि, इस बीच दिल्ली की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती रही और दिल्ली का 'बचत का बजट' - 'घाटे के बजट' में परिवर्तित हो गया था।

इसके बाद तो लगभग प्रत्येक राज्य में इस प्रकार का दौर ही चल पड़ा। हिमाचल प्रदेश राज्य में कांग्रेस, सेवा निवृत्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के

वादा, राज्य की प्रत्येक वयस्क महिला को 1500 रुपए देने का वादा एवं प्रत्येक परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा कर वर्ष 2022 में सत्ता में आ गई। बाद में जब पुरानी पेंशन योजना को हिमाचल प्रदेश में लागू किया गया तो हिमाचल प्रदेश के पहिले से ही दबाव में चल रहे बजट पर अतिरिक्त बोझ पड़ा एवं राज्य की आर्थिक स्थिति लगभग पूर्णतः डावांडोल हो गई है एवं राज्य को अपने ऋण पर ब्याज का भुगतान करने एवं राज्य के सामान्य खर्चों को चलाने के लिए भी ऋण लेना पड़ रहा है।

इसी चलन को कायम रखते हुए हाल ही में सम्पन्न बिहार राज्य में भी विधान सभा चुनाव के समय श्री नीतीश कुमार की राज्य सरकार ने राज्य की 1.21 करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में 10,000 रुपए की राशि सीधे जमा करवाई है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की घोषणा 29 अगस्त 2025 को की गई थी एवं केवल एक माह के अंदर इस योजना को लागू कर दिया गया तथा राज्य की महिलाओं के बैंक खातों में राशि हस्तांतरित कर दी गई। हालांकि, राज्य में लागू की गई इस योजना को महिला सशक्तिकरण की सबसे बड़ी पहल के रूप में देखा गया क्योंकि राज्य सरकार द्वारा इस योजना को लागू करने का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना एवं रोजगार के नए अवसर निर्मित करना था। ऐसा बताया गया है कि राज्य की कुछ महिलाओं ने इस राशि से अपनी छोटी छोटी उत्पादन इकाईयों को प्रारम्भ करने में सफलता पाई है। राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि बिहार सरकार उन महिलाओं को रुपए 2 लाख तक की सहायता राशि उपलब्ध कराएगी जिनका व्यवसाय सफल रहेगा, इस छोटे निवेश से पूरा परिवार लाभान्वित होगा। बिहार राज्य में लगभग 1.40 करोड़ जीविका दीदियां स्व सहायता समूहों के माध्यम से सक्रिय हैं। आज देश के सबसे बड़े राज्यों में बिहार राज्य में गरीब वर्ग के नागरिकों की संख्या सबसे अधिक है एवं बिहार राज्य के नागरिक रोजगार प्राप्त करने के उद्देश्य से सबसे अधिक पलायन करते हुए दिखाई देते हैं। पूर्व में उत्तर प्रदेश राज्य की भी लगभग यही स्थिति थी, परंतु, हाल ही के समय में उत्तर प्रदेश राज्य में रोजगार के पर्याप्त नए अवसर निर्मित हुए हैं जिससे इस राज्य में नागरिकों का रोजगार के लिए पलायन रुका है। यदि बिहार राज्य भी अपने नागरिकों का पलायन रोकने में सफल रहता है एवं अपने राज्य के नागरिकों के लिए पर्याप्त मात्रा में रोजगार के नए अवसर निर्मित करने में सफलता प्राप्त करता है तो यह देश के आर्थिक विकास को भी गति देने में सहायक होगा। परंतु, लाख टके का प्रश्न यह है कि क्या बिहार सरकार की आर्थिक स्थिति उक्त प्रकार की योजनाओं को चलाने की स्थिति में है?

इसी प्रकार, मध्य प्रदेश राज्य भी लाड़ली बहिना योजना को लागू कर चुका है एवं इसी तर्ज पर हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, आदि राज्यों में भी नागरिकों को मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजनाएं प्रारम्भ की गई। तमिलनाडु में तो मुफ्त में सुविधाएं उपलब्ध कराने का पुराना इतिहास रहा है। कुछ राज्यों में तो टीवी, लैपटॉप, स्कूटी, साइकल, आदि जैसे महंगे उत्पाद भी चुनावों के समस्त राज्य के नागरिकों को मुफ्त में उपलब्ध कराए जाते रहे हैं। विभिन्न राज्यों द्वारा यदि चुनाव जीतने के लिए राज्य के नागरिकों को मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध कराने का क्रम यदि जारी रहता है तो यह प्रचलन इन राज्यों एवं देश के लिए उचित नहीं कहा जा सकता है क्योंकि आज सब्सिडी, वेतन, पेन्शन एवं ब्याज जैसी मदों पर लगातार बढ़ रहे खर्चों के कारण 15 राज्यों का बजटीय घाटा कानूनी रूप से निर्धारित 3 प्रतिशत की सीमा से ऊपर हो गया है। हिमाचल प्रदेश में बजटीय घाटा बढ़कर 4.7 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 4.1 प्रतिशत, आंध्रप्रदेश में 4.2 प्रतिशत एवं पंजाब में 3.8 प्रतिशत के खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश के कई राज्यों ने अपने पूंजीगत खर्च को घटाया है। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2022-23 के बीच राज्यों ने अपने पूंजीगत खर्च में 51 प्रतिशत तक की कमी की है। दिल्ली में 38 प्रतिशत, पंजाब में 40 प्रतिशत, आंध्रप्रदेश में 41 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 33 प्रतिशत से पूंजीगत खर्चों में कमी दर्ज हुई है। आज कई राज्य सरकारें सब्सिडी प्रदान करने की मद पर अपने खर्चों को लगातार बढ़ा रहीं हैं एवं पूंजीगत खर्चों को लगातार घटा रही हैं, जो उचित नीति नहीं कही जा सकती है। इस प्रकार तो इन राज्यों की अर्थव्यवस्थाएं शीघ्र ही डूबने के कगार पर पहुंच जाने वाली हैं।

अब यदि चुनाव जीतने के लिए विभिन्न राज्य सरकारें क्या इसी तरह की योजनाओं को लागू करती रहेंगी। यदि हां, तो इन राज्यों को अपने दिवालिया होने के लिए बहुत लम्बा इन्तजार नहीं करना होगा। क्योंकि, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी एक प्रतिवेदन में बताया गया है कि विशेष रूप से पंजाब, केरल, पश्चिमी बंगाल, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, बिहार, दिल्ली आदि राज्यों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। यदि समय पर इन राज्यों के आर्थिक ढांचे को सुधारने के प्रयास नहीं किया गए तो यह राज्य दिवालिया होने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि, समय समय पर केंद्र सरकार द्वारा सहायता की राशि उपलब्ध कराकर कई राज्यों की वित्तीय कठिनाईयों को हल करने का प्रयास किया जाता है परंतु, केंद्र सरकार भी लम्बे समय तक यह कार्य नहीं कर सकती है क्योंकि अंततः इससे केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति पर भी दबाव बनता है।

विभिन्न राज्यों के वित्तीय घाटे की स्थिति एवं प्रवृत्ति पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर इस पर रोक लगने का समय अब आ गया है। उत्पादक कार्यों पर सब्सिडी दी जाय तो ठीक है परंतु यदि यह लोक लुभावन वायदों को पूरा करने पर दी जा रही है तो इन पर अब अंकुश लगाया जाना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा आगे बढ़कर इस सम्बंध में कुछ नियम जरूर बनाए जाने चाहिए। यदि इन राज्यों की वित्तीय स्थिति लोक लुभावन घोषणाओं को पूरा करने की नहीं है तो, इस प्रकार की घोषणाएं चिन्हित राज्यों द्वारा नहीं की जानी चाहिए, ऐसे नियम बनाए जाने चाहिए। सहायता की राशि केवल चिन्हित व्यक्तियों को ही प्रदान की जानी चाहिए न कि राज्य की पूरी जनता को उपलब्ध करायी जाय।

जैसा कि बिजली माफी योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। राज्य के समस्त परिवारों को 300/400 यूनिट बिजली मुफ्त में उपलब्ध कराए जाने के प्रयास हो रहे हैं। यदि राज्य की आर्थिक हालत बिगड़ रही है तो इसका खामियाजा भी अंततः उस प्रदेश की जनता को ही भुगतना पड़ता है। यह राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, आदि मदों पर होने वाले खर्च में कटौती करते हैं, जो राज्य के आर्थिक विकास एवं भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए ठीक नहीं है। राज्य में आर्थिक विकास की गति कम होने से इन राज्यों में रोजगार के अधिक अवसर भी निर्मित नहीं हो पा रहे है।

जीवन में एक ही मित्र काफ़ी होता है जो हर संकट में कंधे से कंधा मिला कर चले

सच्चा मित्र वही होता है जो कभी भेदभाव नहीं करता मित्र गलत भी हो तब भी साथ नहीं छोड़ताद्य जीवन मे एक ही मित्र काफ़ी होता है जो हर संकट मे कंधे से कंधा मिला कर चले और कहे दोस्त कोई बात नहीं मै हूँ न घबराओ मत अंतिम सांस तक साथ निभाउंगाद्य आधुनिक इंटरनेट युग में ऐसे दोस्त विलुप्त हो चुके हैंद्य आज मतलबी दोस्त हो गए हैं मतलब खत्म दोस्ती खत्म हो जाती हैद्य दोस्ती निस्वार्थ होनी चाहिए स्वार्थ नहीं होना चाहिएद्य अक्सर देखा गया है की आज मतलबी दोस्तों की संख्या बढ़ती जा रही है ऐसे उदाहारण बहुत हैं की जो लोग कभी सच्चे दोस्त थे आज अच्छी जॉब पर लग गए तो अपने दोस्तों को भूल गए और पहचानने से इंकार करते हैं लेकिन इतिहास साक्षी है की जो अपनी औकात भूल जाते हैं वक़्त उनको तहस नहस कर देता हैद्य नए नए दोस्त जब बन जाते हैं तो पुराने दोस्त भुला दिए जाते हैं एक शायर ने कहा था की जिंदगी में हर चीज अच्छी होती है लेकिन दोस्त पुराने ही अच्छे होते हैं जो हर परिस्थिति से वाकिफ होते हैंद्य नए दोस्त सिर्फ नौ दिन चलते हैं जबकि पुराने ताउम्र चलते हैंद्य आज कुछ लोग अमीर बन गए तो पुराने दोस्तों को अनदेखा करते हैं अपना समय भूल गए हैंद्य गरीब के साथ रिश्ता छुपाते हैंद्य गरीब का स्वाभिमान बहुत बड़ा होता है वह स्वाभिमान से जीता है किसी को इग्नोर नहीं करता दिन रात बिना स्वार्थ के तत्पर रहता है लेकिन लोग उसका आदर नहीं करतेद्य गरीब आदमी बेईमान नहीं होता नमक से खा लेता है किसी के आगे हाथ नहीं फैलाताद्य भाग्य अपना अपना है कोई झोपड़ी में खुश है तो महलों में भी रोता हैद्य भाग्य किसी की बपोती नहीं होती कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है अच्छे कर्म करते रहिएद्य अपना अपना भाग्य होता है जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगाद्य कर्म प्रधान होता है इसलिए कर्म करते रहिएद्य भाग्य किसी क़ो भी मिट्टी में मिला सकता हैद्य भाग्य एक पल में किसी क़ो कंगाल बना दे यह किसी क़ो पता नहीं होताद्य दो जून की रोटी क़ो तरसने वाले आज अपना समय भूल चुके हैंद्य अच्छे कर्म जीवन क़ो स्वर्ग बना देते हैं और बुरे कर्म जीवन क़ो नर्क बना देते हैंद्य मानव क़ो अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिएद्य आज कुछेक तथाकथित लोग तिगड़म करके ऐसे पदों पर विराजमान है जिसके वे काबिल नहीं है लेकिन सिफारिश के बलबूते स्थान हासिल करने वालों को एक दिन वक्त जरुर धूल चटाता है अरस्तु ने कहा था की जो सबका मित्र होता है वह किसी का मित्र नहीं होता वर्तमान परिपेक्षय में यह बात चरितार्थ हो रही हैद्य कुछ लोग सबके साथ मित्रता रखते हैं लेकिन किसी के भी सच्चे मित्र नहीं हैंद्य सबको बेबकूफ बनाते हैं लेकिन ऐसा ज्यादा दिन नहीं चलता है एक दिन ऐसे लोगों का पर्दाफाश हो जाता हैद्य ऐसे लोग गिरगिट प्रजाति के होते हैं यह इधर की बातें उधर करते हैंद्य ग़लतफहमीयां पैदा करते हैंद्य ऐसे लोग मौकापरस्त होत्ते हैं ऐसे लोगों का विश्वास नहीं करना चाहिए क्यूंकि ऐसे लोगों का कोई दिन मान नहीं होते यह अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी की भी बलि दे सकते हैं ऐसे दोहरी मानसिकता वाले लोगों से समय रहते किनारा कर लेना चाहिए ऐसे लोग बहुत ही घातक होते हैंद्य यह दोस्तों में दरार डालते हैंद्य दोस्ती बराबर की न हो तो टूट जाती है एक विचारक ने कहा था की दोस्ती बराबर की होनी चाहिए अगर दोस्ती बराबर की न हो तो टूट जाती हैद्य आजकल दोस्ती हैसियत देखकर की जाती है की उसका जीवन स्तर कितना ऊँचा है स्टेटस क्या है क्या जॉब करता है क्या उसके पास गाड़ी है बंगला है आलीशान मकान है यह दोस्ती का पैमाना हैद्य ग़रीब अमीर की दोस्ती बहुत कम होती है क्यूंकि अमीर अपनी पैसे की धौंस जमाते है और गरीबों को दबाते हैं इग्नोर करते हैं और नीचा दिखाते हैंद्य कहते हैं सच्चे व पक्के दोस्त नसीब वालों को ही मिलते हैं आज सच्चे मित्र मिलना बहुत ही कठिन हैद्य वास्तव में सच्चा मित्र वह होता है जो हमेशा हर दुःख सुख व मुसीबत में हमारे साथ खड़ा रहता हैद्य सुख दुःख जीवन की धूप छावं होते हैं और जीवन में इनका आना जाना एक सतत प्रक्रिया हैद्य जब वह प्रतिभा के आगे नहीं टिकता एक कहावत की घर का जोगड़ा

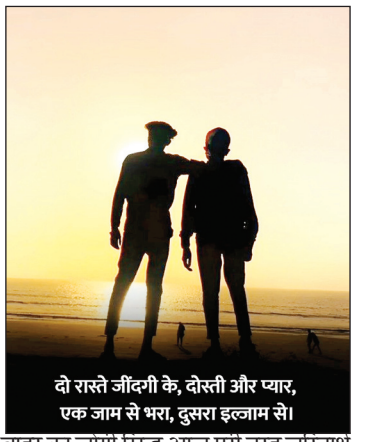

बाहर का जोगी सिद्ध आज पूरी तरह चरितार्थ हो रही है। मगर मानव को एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि मुसीबत में अपने ही काम आते है बाहर के तमाशा देखते हैं। आज अपनों को नीचे गिराया जाता है और बाहर के लोगों को उपर उठाया जाता है भेदभाव किया जाता है प्रतिभा को दबाया जाता है और चंद स्वार्थों के लिए बाहर के लोगों को फायदा पहुंचाया जाता है। आज कितने ही प्रतिभावान लोग है जिन्हे दरकिनार करके अयोग्य लोगों को मौका दिया जाता है।अनुभवहीन लोग आज इतने बड़े बन जाते है कि दूसरों को पाठ पढ़ाने लगते है कि कौन काम सही है और कौन गलत मगर सच्चाई सौ परदे फाड़ कर बाहर आती है तब ऐसे लोग खाक में मिल जाते है यह वक्त का कैसा तकाजा है कि आज सच्चे व इरादों के पक्के लोगों को मुख्यधारा से बाहर किया जा रहा हैं । मगर वक्त एक ऐसा तराजू है जिसके एक पलड़े में जिन्दगी और दूसरे पलड़े में मौत होती है जीवन और मृत्यु में सिर्फ सांसों का फासला है।जब इन्सान जिन्दा होता है तो कोई उसका हाल तक नहीं पूछता लेकिन जब संसार से रुखस्त हो जाता है तो हर आदमी मातम में शामिल होने में अपनी शान समझतें है। जिन्होने जब जिन्दा था तो बात तक नहीं की होंगी।

जब जीता है तो एक जोड़ी कपड़ा तक नसीब नहीं होता मगर जब उसके किसी काम का नहीं होता उसके मृत शरीर पर सैंकड़ों चादरें डाली जाती है।जीते जी जिसे घी नहीं मिलता जलाती बार मुहं में शुद्ध देशी घी की आहुती दी जाती है जो व्यर्थ है।कहने का तात्पर्य यह है कि मानव की जीते जी सहायता कि जाए तो वही सच्ची मानवता कहलाएगीद्य आत्मकेन्द्रित लोग बहुत ही घातक होते हैं बस अपना काम हो जाए दुनिया भाड़ में जाए।समाज में ऐसे लोग किसी क़े नहीं होते है।आज भूखी जुएं अपनी औकात भूलकर ऐसे इतराती है कि जैसे खानदानी रईस हो पर वक्त के पास हर आदमी का लेखा-जोखा है कि कौन रईस था और कौन दाने-दाने को मोहताज था। किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए हर आदमी से समानता का व्यवहार करना चाहिए

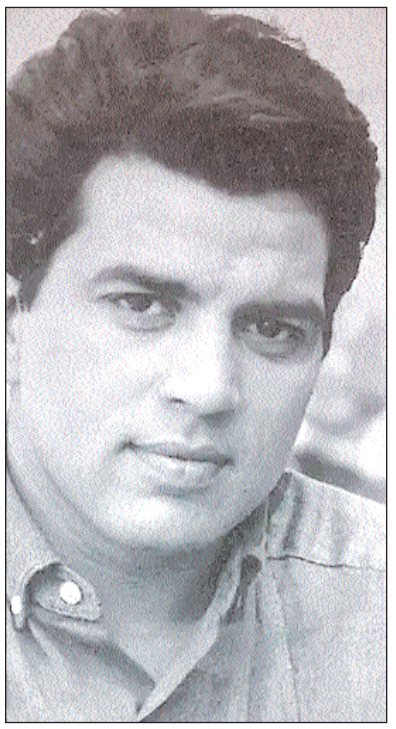

टूट गई जय-वीरू की जोड़ी

अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन

मुंबई।

दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है। 89 साल के धर्मेंद्र ने सोमवार दोपहर अपने घर पर अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार विले पार्ले श्मशान भूमि में हुआ, जिसमें सलमान खान, संजय दत्त, अमिताभ बच्चन, आमिर खान समेत कई सेलेब्स पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन को एक युग के अंत का संकेत कहा है।

धर्मेंद्र के परिवार ने उनके निधन की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की। दोपहर में उनके घर के बाहर एम्बुलेंस पहुंची थी और विले पार्ले श्मशान भूमि में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। इसके बाद उनका पार्थिव शरीर एम्बुलेंस से श्मशान घाट पहुंचाया गया। धर्मेंद्र कुछ समय से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। 10 नवंबर को उन्हें सांस लेने में दिक्कत आई थी, जिसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती किया गया। इस दौरान उन्हें वेंटिलेटर में रखा गया। मीडिया में उनके निधन की खबर भी आई, जिसे परिवार ने नकार दिया। 12 नवंबर को धर्मेंद्र को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था और डॉक्टरों ने घर पर ही उनके आगे के इलाज की बात कही थी।

राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य राजनीतिक हस्तियों ने सोशल मीडिया पर अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन को एक युग के अंत का संकेत कहा है।

जब घंटों तक यूनीट को धर्मेंद्र ने बेवकूफ बनाया

कम लोग जानते हैं कि धर्मेंद्र ने शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र यूनीट के साथ बड़ी हंसी मजाक करते थे और कभी कभी तो उन्हें उल्लू भी बना दिया करते थे। दरअसल धरम पाजी अपनी एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे जब उन्हें बीयर पीनी थी और उन्होंने प्रोडक्शन स्टाफ से कहा कि वहां एक ऐसा झाग तैयार करें जिससे देखने वाले को लगे कि मैं ग्लास में बीयर नहीं बल्कि लस्सी पी रहा हूं। ऐसा ही हुआ और धर्मेंद्र सेट पर बड़े मजे से अपनी बीयर पीते रहे थे, लेकिन देखने वाले उसे लस्सी समझते रहे

राजनीतिक दलों को 2 हजार तक के कैश डोनेशन की छूट क्यों

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को उस रिट याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें राजनीतिक दलों के चंदे में पारदर्शिता की मांग उठाई गई थी। साथ ही राजनीतिक दलों की तरफ से दाखिल इनकम टैक्स रिटर्न और चंदा रिपोर्ट में बड़ा अंतर होने का भी आरोप लगाया गया था। याचिकाकर्ता ने इनकम टैक्स अधिनियम के उस प्रावधान को चुनौती दी है, जो राजनीतिक दलों को 2000 रुपये तक का नकद डोनेशन दिए जाने की परमिशन देता है। उसका दावा है कि देशभर में हर जगह डिजिटल पेमेंट बहुत ही बढ़िया तरीके से हो रहा है, फिर 2000 रुपये तक के नकद चंदे की परमिशन दिए जाने का कोई औचित्य नहीं है।

आज कुआं प्यासे के पास आया है... सीएम ने पंचायतों को बताया विकास का आधार

भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में सोमवार को राज्य स्तरीय कार्यशाला-वॉटर शेड सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने जल गंगा संवर्धन अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम की थीम आत्मनिर्भर पंचायत समृद्ध मध्यप्रदेश रखी गई है। यह कार्यशाला 26 नवंबर तक कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कंन्वेंशन सेंटर में आयोजित होगी। 3 दिवसीय कार्यशाला में 2000 से ज्यादा जनप्रतिनिधि, अधिकारी और विषय विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम में सीएम डॉ. मोहन ने जल संवर्धन के लिए काम करने वाले अधिकारियों की जमकर प्रशंसा की। कार्यशाला के दौरान उन्होंने कहा कि आज प्यासा कुएं के पास नहीं आया है, कुआं प्यासे के पास आया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे यहां शासन की अद्भुत परंपरा है। शासन गांव से जुड़कर सच्चे अर्थों में भारत को मजबूती प्रदान करता है। महात्मा गांधी के शब्दों में कहा जाए तो भारत की आत्मा ग्रामीण अंचल में बसती है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन करने की पद्धति और उनके सुशासन के दृष्टिकोण ने भारत को अलग पहचान दिलाई है। हम कल्पना कर सकते हैं कि साल 2047 का अमृतकाल कैसा होगा। हमारी सरकार लगातार इस पर मंथन कर रही है कि जिला पंचायतें, पंचायतें, जनपद पंचायतें किस तरह से आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि आदिकाल से हमारे समाज में ऑटोनोमी को स्थान दिया गया है। इसलिए शासन की स्वशासी व्यवस्थाओं में पंचायतों को अधिकार संपन्न बनाना जरूरी है। हमें चुनी हुई इकाइयों को इतना सशक्त करना होगा कि वे विकास में अपनी भूमिका मजबूती से अदा कर सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का भाव आपकी कठिनाइयों को समझकर उसका हल निकालना है। आज प्यासा कुएं के पास नहीं आया है, कुआं प्यासे के पास आया है।<

सरकार आपकी सारी जरूरतें पूरी करेगी। उन्होंने कहा कि हमारे यहां शुरू से ही तालाब, पोखर, बावड़ी, कुएं की व्यवस्था थी। लेकिन, हमें इन्हें सहेजने के काम को कर्म कांड की तरह नहीं लिया, बल्कि तीन महीने तक सतत अभियान चलाया। इन्हीं की बदौलत राज्य को पुरस्कार मिले। पानी की बूंद-बूंद अहम है।

राबड़ी देवी की जज बदलने वाली मांग की याचिका खारिज

नई दिल्ली। आईआरसीटीसी घोटाले में आरोपी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में एक नई याचिका दाखिल की है। उन्होंने इस मामले की सुनवाई कर रहे जज विशाल गोगने को बदलने की मांग की है। इस अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई संभव है। गौरतलब है कि इसी साल अक्टूबर 2025 में अदालत ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव सहित कुल 14 आरोपियों पर आरोप तय किए थे। दैनिक सुनवाई पर लालू-राबड़ी की आपत्ति पहले ही खारिज राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को हाल ही में एक और झटका लगा था। नवंबर में अदालत ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया था।

देश के 53वें चीफ जस्टिस बने जस्टिस सूर्यकांत, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ

नई दिल्ली।

जस्टिस सूर्यकांत सोमवार को भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद वह देश के लिए 53वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 24 नवम्बर सोमवार को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में भारत के नए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को पद की शपथ दिलाई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई समेत कई गणमान्य मौजूद रहे।

जस्टिस सूर्यकांत ने सीजेआई भूषण आर गवई की जगह ली है। राष्ट्रपति मुर्मू ने सीजेआई गवई की सिफारिश के बाद संविधान के आर्टिकल 124 के क्लॉज (2) द्वारा दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जस्टिस सूर्यकांत को भारत का अगला चीफ जस्टिस नियुक्त किया। जस्टिस सूर्यकांत का जन्म 10 फरवरी, 1962 को हरियाणा के एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। उन्होंने 1984 में हिसार से अपनी लॉ यात्रा शुरू की और फिर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए चंडीगढ़ चले गए। इस दौरान उन्होंने कई तरह के संवैधानिक, सर्विस और सिविल मामलों को संभाला, जिसमें यूनिवर्सिटी, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, बैंक और यहां तक कि खुद हाईकोर्ट को भी रिप्रेजेंट किया। जुलाई 2000 में उन्हें हरियाणा का सबसे कम उम्र का एडवोकेट जनरल बनाया गया। इसके बाद, 2001 में उन्हें सीनियर एडवोकेट बनाया गया और 9 जनवरी 2004 को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का परमानेंट जज बनाया गया। बाद में, उन्होंने अक्टूबर 2018 से 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट में अपनी पदोन्नति तक हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर काम किया।

नए सीजेआई के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में नहीं पहुंचे राहुल गांधी, भाजपा ने उठाए सवाल

देश के नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत की शपथ ग्रहण कार्यक्रम में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की गैर मौजूदगी को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं. बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए राहुल पर निशाना साधा है. गौरतलब है कि राहुल लाल किले पर आयोजित 15 अगस्त के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे थे. भंडारी ने अपने पोस्ट में लिखा है कि भारत के नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में राहुल गांधी क्यों शामिल नहीं हुए? उन्होंने सवाल उठाते हुए पूछा कि बतौर लोकसभा में विपक्ष के नेता की कार्यवाही में बाधा पहुंचाने, संवैधानिक पदों के लिए होने वाले शपथ ग्रहण समारोह से दूर रहने के अलावा राहुल ने बतौर विपक्ष के नेता और क्या महत्वपूर्ण काम किया है।

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक अभिषेक साहू द्वारा राजा आफसेट 863/9 नेहरु नगर इंदौर से मुद्रित एवं युग प्रभात कार्यालय 10 प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित,सम्पादक अभिषेक साहू
मो. नं. 9920999817, भारत सरकार समाचार पत्र पंजीयन संख्या - 38189/72, डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/58/2024-2026 Yugindore@gmail.com